अब हर रोज दर्पण
3

जबलपुर बुधवार 16 सितंबर 2026 > शक संवत 1948, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, पंचमी

वर्ष 32 अंक 79 मूल्य ₹3.00 > पेज 08 > आर.एन.आई. पंजीयन नम्बर 64561/96

www.swatantramat.com

स्वतंत्र मत

स्वतंत्र मत में विज्ञापन देने के लिए 9589920250 पर कॉल करें * स्वतंत्र मत का अंक प्राप्त करने के लिए 9301359695 पर कॉल करें।

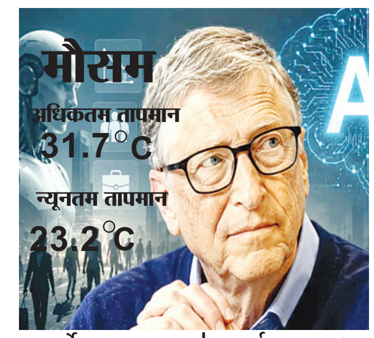

सूर्योदय - 5.57 | सूर्यास्त - 6.13

कान्हीवाड़ा और बरघाट में जनविश्वास की... 5

1000 दिवस से अधिक समय तक सीएम हेल्पलाइन... 6

डॉक्टर से मारपीट पर चिकित्सकों में आक्रोश... 7

सितमगर सितम्बर...सड़कें बनीं समन्दर

गुजरात के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात

अहमदाबाद

गुजरात में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। अहमदाबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से भारी बारिश जारी है। अहमदाबाद में सोमवार सुबह से हुई बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच शहर में औसतन 3 इंच बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के माणेकबाग चौराहे पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया। सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। हालात ऐसे बने कि सड़क और पानी के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। कई जगह गाड़ियां और टू-व्हीलर पानी में फंसकर बंद हो गए। अहमदाबाद में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। दिन के समय भी कई हिस्सों में अंधेरा जैसा माहौल बना रहा। इसके बाद तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। माणेकबाग चौराहे पर पानी तीन फीट तक पहुंच गया। सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। कई वाहन पानी में फंस गए और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। सुबह करीब 10 से 12 बजे के बीच अहमदाबाद में झमाझम बारिश हुई।

पंचवटी चौराहे के आसपास सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई। बारिश के दौरान वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। बारिश रुकने के बाद भी कई जगह पानी जल्दी नहीं उतरा। इसे लेकर लोगों में अहमदाबाद नगर निगम के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी। जलभराव के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास सरदारनगर रोड से गांधीनगर की ओर जाने वाली सड़क पर भी बारिश का पानी भर गया। सड़क पर जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। शहर के कई अंडरपास में भी पानी भरने की स्थिति बनी। कुछ अंडरपास को बंद करने की नौबत आई। बाद में पंप लगाकर वहां जमा पानी निकालने का काम किया गया। राज्य में सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का असर दिखाई दिया। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में यानी सुबह 6 बजे तक गुजरात के 33 जिलों के 240 तालुकों में बारिश दर्ज की गई।

अभी राहत के आसार नहीं

इसके बाद सोमवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 225 तालुकों में सामान्य से भारी बारिश दर्ज हुई। आनंद के बिरादर में सबसे ज्यादा 5.43 इंच बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के धोलका में 4.02 इंच, वडोदरा के करजन में 3.94 इंच और अहमदाबाद के दसक्रोई में 3.50 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक गुजरात में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद, आनंद, बोटाद, भरूच, बनासकांठा, महेसाणा, पाटन, वाव-थराद, कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, गीर सोमनाथ, जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली और भावनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 जून से 13 सितंबर तक राज्य के अलग-अलग शहरों और जिलों में हुई बारिश के कारण अब तक 85456 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं 9822 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए गुजरात में 9 एनडीआरएफ और 29 एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं।

एलियन की तरह है एआईः बिल गेट्स

इसे काबू करना होगा लेकिन सरकारों के पास कोई प्लान नहीं

नई दिल्ली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस वक्त दुनिया भर में एक तरह का बवाल मचा हुआ है। हर दिन एआई को लेकर ऐसे दावे हो रहे हैं जिससे आम इंसान डरा हुआ है। एक तरफ जहां ओपेनएआई और एंथ्रोपिक के हेड कह रहे हैं कि एआई पर लगाम लगाना होगा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम एआई को रोक नहीं सकते वर्ना चीन आगे निकल जाएगा। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि दुनिया की कोई भी सरकार अभी उन बड़े बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, जो एआई समाज में ला सकता है। उनका कहना है कि एआई से नौकरियों पर असर पड़ सकता है, साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है और लोगों में एआई से बातचीत की लत भी लग सकती है। यानी ये लोगों को एडिक्ट बना सकता है। गेट्स की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब एआई को लेकर दुनिया में बहस तेज हो गई है। एक तरफ कंपनियां ज्यादा ताकतवर एआई बनाने की होड़ में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स और टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम इसके खतरों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। इसी बीच गेट्स ने कहा है कि सरकारों को अब सिर्फ एआई का फायदा देखने के बजाय इसके असर से निपटने की तैयारी भी करनी होगी। हालांकि यहां ये भी समझना जरूरी है कि भले ही एआई कंपनियों के सीईओ स्लोडाउन की बता कर रहे हैं, लेकिन कोई वाकई इसे स्लोडाउन करना चाह नहीं रहा है।

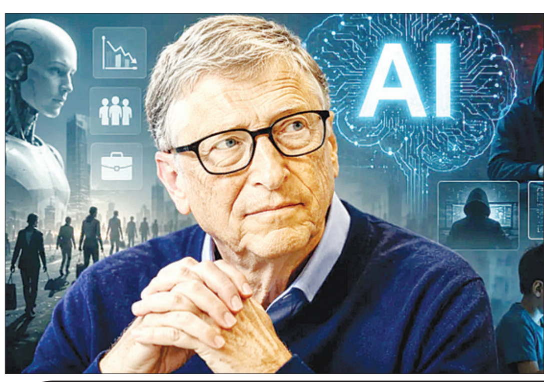

गेट्स ने एआई को एलियन से क्यों जोड़ा

बिल गेट्स ने एआई के भविष्य को समझाने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि एलियन धरती पर हमला करने आता है और उसके बाद अमेरिका, चीन और बाकी देश आपसी मतभेद भूलकर एक साथ आ जाते हैं। गेट्स के मुताबिक एआई कुछ हद तक ऐसा ही मौका है। उनका कहना है कि एआई हमारे सामने आ चुका है और दुनिया को इसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसका सीधा मतलब है कि एआई को लेकर अमेरिका, चीन और दूसरे देशों के बीच सिर्फ प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। कुछ मामलों में उन्हें साथ मिलकर ऐसे नियम बनाने होंगे, जिनसे एआई का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

सबसे बड़ी लड़ाई अमेरिका-चीन के बीच

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने एआई की होड़ में चीन की तेजी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के पास कई ऐसे संस्थान हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतर एआई मॉडल बनाने की क्षमता रखते हैं। बता दें कि कल यानी 14 सितंबर को ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा था कि एआई स्लोडाउन नहीं हो सकता, क्योंकि चीन यही चाहता है। गेट्स के मुताबिक दोनों देशों के सबसे अच्छे एआई मॉडल के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका और चीन के बीच एक तरह की बड़ी एआई प्रतियोगिता बताया है।

बहुत पीछे है सरकारों की तैयारी

बिल गेट्स ने कहा कि कोई भी सरकार एआई से आने वाले बदलावों के लिए उतनी तैयारी नहीं कर रही है, जितनी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारों की तैयारी इस मामले में काफी पीछे है। गेट्स पहले एआई को लेकर काफी उम्मीद जताते रहे हैं। उनका मानना रहा है कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे जरूरी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन अब उनका कहना है कि इसकी रफ्तार के साथ कुछ ऐसे खतरे भी सामने आ रहे हैं, जिनके लिए दुनिया अभी तैयार नहीं है। इनमें सबसे बड़ी चिंता नौकरियों को लेकर है। एआई ऐसे कई काम करने लगा है, जो कुछ साल पहले तक सिर्फ इंसानों के भरोसे थे। एआई ज्यादा काम करने लगेगा तो कई नौकरियों का तरीका बदल सकता है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

42 हजार 490 करोड़ से होगा जनकल्याण

भोपाल (स्वतंत्र मत)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण को गति देने के लिए 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्र प्रवर्तित समग्र शिक्षा योजना की आगामी पांच वर्षों की निरंतरता के लिए 36 हजार 6 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। नागरिक सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य से परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के लिए 1 हजार 166 करोड़ रुपये तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये की निरंतरता अनुमोदित की गई। जल संसाधन के क्षेत्र में उज्जैन की चितावद, सिंगरौली की गौंड तथा अशोकनगर की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए, जिससे 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करते हुए नवगठित जिलों मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में खनिज शाखा की स्थापना के लिए 21 नवीन पदों तथा अनूपपुर व शहडोल के उन्नयित स्कूलों के लिए 36 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। साथ ही रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष सहायता दिए जाने का अनुसमर्थन और मार्कफेड को 2,220 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

सड़क सुरक्षा, जनहित और महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी निरंतरता प्रदान की गई है। कुशल चालकों को तैयार करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है। ग्रामीण अंचलों में बेहतर आवागमन के लिए ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये, सड़क हादसों में पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए नेक व्यक्ति पुरस्कार के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये और सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फंड) के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई है।

असम के 15 कांग्रेस नेता 3 साल के लिए निष्कासित

नई दिल्ली। असम कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने के आरोप में 15 नेताओं और कार्यकर्ताओं को तीन साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी की राज्य इकाई के महासचिव (संगठन) रमन्ना बरुआ द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के निर्देश पर की गई।

उग्रवादियों ने की 2 महिलाओं की हत्या

इंफाल। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने दो कुकी महिलाओं की हत्या कर दी और कई फार्महाउस में आग लगा दी। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय चोंगा सिथलौ और 30 वर्षीय किम्बोई सिंगसन के तौर पर की गई है।

फ्रिज फटने से 4 महिलाओं की मौत

बेंगलुरू। कर्नाटक के बेलगावी में मंगलवार सुबह एक घर में फ्रिज फटने के बाद आग लग गई। हादसे में परिवार की चार महिलाओं की मौत हो गई। घटना चवत गली में सुबह करीब 2.30 बजे हुई। मरने वालों की पहचान गंगा डामोने, शारदा डामोने, प्रिया डामोने और भारती डामोने के रूप में हुई है। दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, ब्लास्ट के बाद फ्रिज आग लगी। जो पूरे घर में तेजी से फैल गई और अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके।

सूचना

स्वतंत्र मत के समस्त प्रतिनिधियों, पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणवश स्वतंत्र मत का आज का अंक 08 पृष्ठों का ही प्रकाशित हो सका है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।

- संपादक

अमेरिका के दबाव में निर्णय ले रही है सरकार : राहुल गांधी

नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपीआई लेनदेन पर संभावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को एक्स पर किए एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने का रास्ता खोल रही है। राहुल गांधी के मुताबिक, ऐसे लेनदेन की संख्या भले ही यूपीआई के कुल लेनदेन का करीब 5 प्रतिशत हो, लेकिन इनका हिस्सा कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में लगभग 65 प्रतिशत है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ग्राहक से सीधे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो दुकानदार पर लगने वाली फीस का बोझ आखिरकार किसकी जेब पर पड़ेगा। राहुल गांधी का तर्क है कि सरकार भले ही कह रही हो कि आम ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन व्यापारी पर लगने वाली फीस का असर अंततः ग्राहकों पर ही पड़ सकता है। उनके मुताबिक, दुकानदार इस अतिरिक्त लागत को

वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल कर सकते हैं और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से इसका भार ग्राहक की जेब पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने बयान में अमेरिकी भुगतान कंपनियों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो-एमडीआर नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ऐसी नीति की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे यूपीआई पर शुल्क लगाने का रास्ता खुल सकता है।

यूएस ट्रेड डील से जोड़कर मोदी सरकार पर हमला

राहुल गांधी ने इस मुद्दे को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भी जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यूएस ट्रेड डील की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने झुक रहे हैं। अपने बयान में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' कहते हुए उन पर अमेरिकी दबाव के आगे 'सरेंडर' करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी की सभा को 5 शर्तों पर मंजूरी

इंदौर। इंदौर में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को आईडीए ने 5 शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। 19 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए आईडीए ने सिर्फ खाली जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। सुरक्षा समेत बाकी व्यवस्थाएं आयोजकों को खुद करनी होंगी। राहुल गांधी 19 सितंबर को इंदौर आएंगे।

राजपाल एक्टिंग में माहिर, भरोसा करना मुश्किल: सीजेआई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आखिरी बार 2 हफ्ते का समय दिया है। यह रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। कोर्ट ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके पुराने रवैये को देखते हुए भरोसा जताने में भी संदेह जाहिर किया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, उनके पुराने रवैये को देखते हुए। कोई उन पर भरोसा कैसे कर सकता है? वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं। कोर्ट में भी वही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रखी है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

फैसला | बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-2 ने दिया निर्णय

शेख हसीना की पार्टी के 7 नेताओं को सजा-ए-मौत

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-2 ने मंगलवार को प्रतिबंधित अवामी लीग के सात वरिष्ठ नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई। इन नेताओं पर 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों, जिन्हें 'जुलाई विद्रोह' के नाम से जाना जाता है, के दौरान हिंसा का निर्देश देने, उसे भड़काने या उसे बढ़ावा देने में भूमिका निभाने का आरोप था। तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरी ने सातों के खिलाफ फैसला सुनाया। सभी आरोपियों पर मुकदमा उनकी गैरमौजूदगी में चला।

ढाका

मौत की सजा पाने वालों में अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन मंत्री ओबैदुल कादेर, संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दीन नसीम और पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात शामिल हैं। इनके अलावा जुबो लीग के अध्यक्ष शेख फजले शम्स परश, महासचिव मैनुल हुसैन खान निखिल, बांग्लादेश छात्र लीग के अध्यक्ष साद्दाम हुसैन और महासचिव शेख वली आसिफ एनान को भी मौत की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल के फैसले के दौरान सातों आरोपियों की ओर से सरकार द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील मौजूद थे। यह मामला 2024 के उन प्रदर्शनों से जुड़ा है, जिनके करीब 10 महीने बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। ट्रिब्यूनल ने 22 जनवरी को सातों आरोपियों के खिलाफ सात आरोप तय किए थे और 17 फरवरी से मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी। आईसीटी-2 ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा का निर्देश देने और उसे भड़काने में उनकी कथित भूमिका की जांच की। इन प्रदर्शनों ने अंततः 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपियों ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए निर्देश जारी किए, भड़काऊ और उकसाने वाले बयान दिए तथा ऐसी बैठकों में हिस्सा लिया, जिनमें हिंसा की योजनाओं पर चर्चा की गई। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं। नवंबर 2025 में ट्रिब्यूनल ने हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी अपराधों के लिए गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी।

किसान मोर्चा की प्रथम बैठक सम्पन्न

मण्डला (स्वतंत्रमत)। प्रधानमंत्री के सेवा संघर्ष और संकल्प के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला की प्रथम संगठनात्मक बैठक जिला कार्यालय में सम्पन्न हुई बैठक में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा उपस्थित रहे बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजीत पांडे ने की। बैठक में आगामी कार्यक्रम संगठन विस्तार किसान हितैषी केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा प्रधानमंत्री मोदी के सेवा संघर्ष और संकल्प के मंत्र के साथ किसान मोर्चा सदस्यता अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और बैठक में किसानों के कल्याण को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। किसान मोर्चा का लक्ष्य है कि जिले के एक-एक किसान को योजनाओं का लाभ मिले। जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मोर्चा भाजपा की रीढ़ है और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें गांव-गांव तक पहुंचना होगा बैठक में जिला महामंत्री किसान मोर्चा मनहरण पटेल, जिला उपाध्यक्ष जिलेसिंग साहू, जिला मंत्री संतोष चन्द्रोल, पारुल पांडे, वीरेंद्र धर दिवेदी जिला उपाध्यक्ष, अनंत राठौर, सुदेश नामदेव, आनंद राजन, अमरजीत सिंह, जिला मिडिया प्रभारी पवन राय सहित जिले के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री एवं जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन

मण्डला (स्वतंत्रमत)। मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव शीघ्र बहाल किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप द्वारा कलेक्टर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में लंबे समय से बंद छात्रसंघ चुनावों को पुन: प्रारंभ करने की मांग उठाई गई। अभाविप ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के साथ-साथ उनमें नेतृत्व क्षमता सामाजिक चेतना एवं संगठनात्मक कौशल विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वर्ष 2017 से छात्रसंघ चुनाव बंद होने के कारण विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं। अभाविप ने मांग की कि उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप शीघ्र पारदर्शी निष्पक्ष एवं समयबद्ध छात्रसंघ चुनाव आयोजित किए जाएं ताकि उच्च शिक्षा परिसरों में लोकतांत्रिक वातावरण एवं विद्यार्थी नेतृत्व को मजबूती मिल सके।

फरार वारंटी आया पकड़ में

मण्डला(स्वतंत्रमत)। पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के निर्देशन में जिले में फरार आरोपियों एवं स्थायी गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर पुलिस को चार वर्ष से फरार स्थायी गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है चौकी हिरदेनगर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 295/22 धारा 25(बी) आर्म्स एक्ट के प्रकरण में पिछले करीब 4 वर्षों से फरार स्थायी गिरफ्तारी वारंटी छगन प्रसाद उर्फ सरोज मरकाम उम्र 36 वर्ष निवासी लुटिया को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर लगा रहे 33 केवी बिजली लाइन

व्यापारियों ने जताई आपत्ति जनसुनवाई में मिले कलेक्टर से

मण्डला(स्वतंत्रमत)।

मंगलवार को नगर के व्यापारी और समाजसेवी कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराने जनसुनवाई पहुंचे। जहां पर कहा कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत चिलमन चौक से बड़ी खैरी तक मुख्य डिंडोरी मार्ग पर 33 केवी उच्चदाब विद्युत लाइन विस्तार कार्य किया जा रहा है। जिस पर नागरिक और व्यापारियों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। कलेक्टर को दिए गए प्रतिवेदन में नागरिकों ने जनसुरक्षा का हवाला देते हुए कार्य को तत्काल स्थगित करने संयुक्त स्थल निरीक्षण कराने तथा विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुरूप लाइन की वास्तविक दूरी का तकनीकी परीक्षण कराने मांग की है प्रतिवेदन के अनुसार चिलमन चौक से बड़ी खैरी तक का मार्ग नगर पालिका क्षेत्र में आता है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में मकान दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान स्थित हैं। वर्तमान में सड़क चौड़ीकरण

तथा भविष्य में फुटपाथ डिवाइडर सहित अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य प्रस्तावित हैं। ऐसे में नागरिकों का कहना है कि 33 केवी उच्चदाब विद्युत लाइन एवं उसके पोल यदि मकानों और दुकानों के अत्यधिक निकट स्थापित किए जाते हैं तो भविष्य में जनसुरक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है नागरिकों ने प्रतिवेदन में कहा है कि 33 केवी विद्युत लाइन उच्च वोल्टेज प्रणाली है। आबादी वाले क्षेत्र में मकान दुकान और सार्वजनिक आवागमन वाले स्थानों के अत्यधिक निकट से ऐसी लाइन गुजरने पर गंभीर विद्युत सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकता है। इस मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक महिलाएं बच्चे बुजुर्ग दुकानदार और राहगीर आवागमन करते हैं। नागरिकों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया तीनों उच्चदाब विद्युत तारों के बीच पर्याप्त और सामान्य दिखाई देने वाली दूरी नहीं रखे जाने की स्थिति सामने आई है उन्होंने पूर्व में अन्य स्थानों पर स्थापित 33 केवी लाइनों का हवाला देते हुए कहा कि वहां तीनों तारों के बीच अपेक्षाकृत पर्याप्त दूरी रखी जाती है जबकि वर्तमान निर्माण में तारों को छोटे लोहे के टुकड़े अथवा क्रॉस-आर्म सपोर्ट के माध्यम से कम दूरी पर व्यवस्थित किया गया प्रतीत होता है। इससे निर्धारित विद्युत सुरक्षा मानकों और आवश्यक फेज-टू-फेज क्लियरेंस के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं प्रतिवेदन में मांग की गई है कि संबंधित विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारी मौके पर पहुंचकर तीनों तारों के बीच वास्तविक दूरी का मापन करें तथा क्रॉस-आर्म सपोर्ट कंडक्टर व्यवस्था और अन्य तकनीकी मानकों का परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए नागरिकों ने लाइन और मकानों-दुकानों के बीच की दूरी को भी संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर प्रस्तावित विद्युत लाइन आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों के काफी नजदीक से ले जाई जा रही है। ऐसे में प्रत्येक प्रभावित स्थान पर 33 केवी लाइन और भवनों के बीच वास्तविक क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर सुरक्षा दूरी का विधिवत मापन आवश्यक है यदि किसी स्थान पर निर्धारित सुरक्षा दूरी से कम अंतर पाया जाता है तो वहां काम तत्काल रोककर लाइन का मार्ग परिवर्तित किए जाने की मांग की गई है। 33 केवी लाइन को मकानों और दुकानों से हटाकर सड़क के मध्य प्रस्तावित डिवाइडर क्षेत्र अथवा किसी अन्य सुरक्षित शासकीय मार्ग से ले जाने की संभावना का परीक्षण किया जाए। 33 केवी लाइन की स्वीकृत ड्राइंग एवं ले-आउट लाइन के मार्ग की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति, आवश्यक होने पर नगर पालिका से प्राप्त एनओसी अनुमति लागू विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुसार निर्धारित क्लियरेंस, तीनों कंडक्टरों के बीच निर्धारित एवं वास्तविक दूरी तथा मकानों-दुकानों से निर्धारित और वास्तविक सुरक्षा दूरी की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है इसके साथ ही प्रयुक्त पोल, क्रॉस-आर्म, सपोर्ट और अन्य विद्युत सामग्री की तकनीकी विशिष्टताओं तथा प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण एवं डिवाइडर के साथ विद्युत लाइन के समन्वित नक्शे को भी सामने रखने की मांग की गई है। इस दौरान प्रमोद चौरसिया, जितेन्द्र चौरसिया, समाजसेवी गिरीश चंदानी, अमित चौरसिया, राजकुमार चावला, जगदीश पमनानी, संदीप चौरसिया, बंटी अग्रवाल, मनोज कुमार वरदानी, मनोज चौरसिया, जवाहर लाल नवदीप, अजय वरदानी, श्रीकांत शर्मा सहित अनेक व्यापारी व समाजसेवी कलेक्टर से मिल हैं।

मधुरम की प्रसिद्ध मिठाईयां अब जबलपुर में भी

मण्डला(स्वतंत्रमत)। मंडला में 35 से अधिक वर्षों से स्वाद गुणवत्ता और विश्वास की पहचान बना चुके मधुरम स्वीट्स ने रविवार को जबलपुर में अपने नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। राधा गोविंद हाइट्स बर्गर किंग के बाजू में शास्त्री ब्रिज चौराहा स्थित प्रतिष्ठान का शुभारंभ महाकौशल प्रांत के प्रांत संघ चालक डॉ. प्रदीप दुबे के कर कमलों से किया गया। मधुरम स्वीट्स के संस्थापक बसंत अग्रवाल ने यहां पर परिवार के साथ पूजन अर्चन किया। वही संचालक राकेश अग्रवाल एवं रितेश अग्रवाल ने बताया कि मंडला में वर्षों से ग्राहकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने के बाद अब जबलपुर में भी वही प्रसिद्ध मिठाइयां बेकरी उत्पाद स्वाद गुणवत्ता और अपनापन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिष्ठान की स्थापना का उद्देश्य ग्राहकों तक शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाने के साथ मंडला की पारंपरिक मिठास को जबलपुर तक पहुंचाना है।

शुभारंभ अवसर पर मधुरम परिवार ने कहा कि शुद्धता उनकी पहचान स्वाद उनकी परंपरा और विश्वास उनकी पूंजी है। 35 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ ग्राहकों का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। नए प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर मधुरम परिवार ने जबलपुरवासियों से अपील की कि वे एक बार जरूर आए और हमे अपना स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान करें।

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन

मण्डला(स्वतंत्रमत)।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के निष्पादन ई-केवाईसी पंजीयन एवं व्यक्तिगत दायित्व से पटवारी संवर्ग को पूर्णत: पृथक रखने मांग की है। इस संबंध में संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष गीतेन्द्र गीतू बैरागी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण मानचित्रण एवं तकनीकी कार्यों में पटवारियों ने सहयोगात्मक भूमिका निभाई है। ऐसे में अब उन्हें पंजीयन दस्तावेजों का व्यक्तिगत निष्पादक बनाया जाना उचित नहीं है।

दस्तावेजों में पटवारी का नाम पद पहचान एवं ई-सिग्नेचर दर्ज होने से भविष्य में सीमा क्षेत्रफल नामांतरण वारिसान हिस्सेदारी कब्जे अथवा सर्वेक्षण संबंधी विवादों में व्यक्तिगत कानूनी दायित्व पटवारी पर आने की आशंका है। संघ ने फार्मर आईडी कार्य में पटवारियों पर दबाव एवं कार्रवाई रोकने मांग भी की। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के पटवारियों ने कम समय में बड़ी संख्या में फार्मर आईडी बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शेष कार्य तकनीकी समस्याओं के निराकरण के साथ निरंतर प्रक्रिया में किया जाना चाहिए। जिओ टैग गिरदावरी को भी संघ ने अव्यवहारिक बताते हुए इसके समाप्त होने तक गिरदावरी कार्य से विरत रहने की बात कही। साथ ही वेतन विसंगति, ग्रेड-पे, कैडर रिव्यू एवं पदोन्नति जैसी लंबित सेवा संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। संघ ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर से पटवारी स्वामित्व योजना में निष्पादक के दायित्व से विरत रहेंगे। अत्यधिक दबाव बनाए जाने पर प्रदेशव्यापी कलमबंद आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान जिले भर के पटवारी उपस्थित रहे।

बिछिया में मवेशियों के अवैध परिवहन पर कार्यवाही

मण्डला/बिछिया(स्वतंत्रमत)। जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशियों के अवैध एवं क्रूरतापूर्वक परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान तीन संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली जिसमें कुल 22 मवेशी बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों वाहनों समेत कुल 32 लाख 95 हजार रुपये का सामान जब्त किया है। मामले में छह आरोपियों के खिलाफ तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार 15 सितंबर की सुबह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ वाहनों के माध्यम से मवेशियों का अवैध एवं नियम विरुद्ध तरीके से परिवहन किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना बिछिया पुलिस ने नेशनल हाईवे पर वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान अलग-अलग समय पर तीन संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। पुलिस ने मवेशियों के परिवहन से संबंधित दस्तावेजों एवं वाहन की स्थिति की जांच की जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस ने मामले में अमित कुमार साहू, सनुप लाल यादव, जावेद खान, अफसर खान, मोहम्मद आसिफ खान और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम तथा मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद बरामद किए गए सभी 22 मवेशियों को बिछिया के कांजीहाउस में सुरक्षित रखा गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी रंजीत सिंह सैयाम, उप निरीक्षक सुरेश कुमार विजयवार, प्रधान आरक्षक विवेक दुबे, प्रधान आरक्षक जितेंद्र परते, आरक्षक रोशन तेकाम, तेवेंद्र, सैनिक महावीर, महेश तथा एसएसयू बल की भूमिका रही।

कान्हा में लगा हाथी रिजुविनेशन कैंप

मण्डला(स्वतंत्रमत)। कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय हाथियों के प्रबंधन का एक दीर्घ इतिहास रहा है। वर्तमान में रिजर्व में कुल 16 विभागीय हाथी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ हाथियों को देश के विभिन्न हाथी मेलों से क्रय कर लाया गया है जबकि कुछ हाथियों का जन्म कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही हुआ है। प्रारंभ से ही इन हाथियों का उपयोग मुख्यत: काष्ठ परिवहन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु गश्ती कार्यों में किया जाता रहा है। कालांतर में इनका उपयोग पर्यटन प्रबंधन में भी किया जाने लगा। हाथियों उनके महावतों तथा उनसे संबद्ध कर्मचारियों द्वारा वर्षभर किए जाने वाले कठिन परिश्रम के फलस्वरूप उत्पन्न थकान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाथियों को विश्राम एवं विशेष स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह का च्व्हाथी रिजुविनेशन (पुनर्यौवनकरण) सप्ताहज्ज् आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथी रिजुविनेशन कैंप का शुभारंभ 15 सितंबर को सूपखार परिक्षेत्र में किया जाएगा तथा इसका समापन 20 सितंबर को होगा। इस अवधि के दौरान सभी 16 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष देखरेख एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के आदेश की जेई कर रहा अव्हेलना

फ्लैट रेट की जगह स्मार्ट मीटर, स्थानीय कृषक परेशान

नैनपुर (स्वतंत्र मत)। कृषि पंपों की बिजली को लेकर नैनपुर के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि वर्षों से फ्लैट रेट योजना के तहत बिजली बिल जमा करने वाले कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर अब स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। इसके बाद बिलिंग व्यवस्था बदल गई और कई किसानों को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राशि के बिल मिलने लगे। किसानों ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विद्युत विभाग से जवाब और बिलों की जांच की मांग की है। किसानों के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लघु एवं सीमांत किसानों को राहत देने के लिए 3 एचपी और 5 एचपी के स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों के लिए फ्लैट रेट योजना लागू की गई थी। नैनपुर के किसान भी लंबे समय से इस व्यवस्था के तहत बिल जमा करते आ रहे थे। किसानों का कहना है कि अब उनके कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाकर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। उनका सवाल है कि फ्लैट रेट व्यवस्था में बदलाव किस आदेश के तहत किया गया और इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को पहले क्यों नहीं दी गई।

अगस्त में 10 हजार रूपये तक का भार-कृषकों का कहना है कि मई 2026 से उन्हें हर माह करीब 2 हजार रुपए के बिल प्राप्त होने लगे। पहले वे छह माह में लगभग 1500 रुपए का बिल जमा करते थे। इसके बाद बिल की राशि लगातार बढ़ती गई। किसानों के अनुसार अगस्त में कुछ उपभोक्ताओं के बिल 6 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक पहुंच गए हैं। किसानों का कहना है कि बरसात के मौसम में खेतों में विद्युत पंपों के संचालन की स्थिति भी सामान्य नहीं रहती, ऐसे में इतनी अधिक यूनिट की खपत दिखना उन्हें समझ से परे है। उन्होंने स्मार्ट मीटर की रीडिंग, पुराने बिल और नए बिलों की स्वतंत्र रूप से जांच कराने की मांग की है।

मीटर लगाने की प्रक्रिया पर सवाल-कृषकों का आरोप है कि खेतों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के दौरान उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि मीटर किस आदेश के तहत लगाए जा रहे हैं और इसके बाद बिलिंग व्यवस्था में क्या बदलाव होगा। किसानों का कहना है कि यदि शासन की योजना में कोई परिवर्तन किया गया है तो इसकी स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए थी।

शिकायत पर कनेक्शन काटने की बात-किसानों ने नैनपुर विद्युत विभाग के जेई रीतेश कुमार वनवारी से भी बिलों की समस्या को लेकर संपर्क किया। किसानों का आरोप है कि शिकायत करने पर उन्हें संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की बात कही जाती है। किसानों ने मांग की है कि विभाग पहले विवादित बिलों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे। इस संबंध में विद्युत विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

जनसुनवाई में पहुंचे किसान

मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में किसानों ने एसडीएम आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर के सामने अपनी समस्या रखी। किसानों ने बताया कि वे वर्षों से शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार छह माह में लगभग 1500 रुपए का बिल जमा करते आ रहे हैं, लेकिन मई 2026 से उन्हें हर माह करीब 2 हजार रुपए के बिल मिलने लगे। किसानों के अनुसार एसडीएम ने मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

अब सामूहिक विरोध की तैयारी

लगातार बढ़ते बिजली बिलों से परेशान किसानों ने अब मामले को लेकर एकजुट होने का निर्णय लिया है। किसानों का कहना है कि वे विद्युत विभाग से फ्लैट रेट योजना की स्थिति स्पष्ट करने, स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश की जानकारी देने, पुराने और नए बिलों की जांच कराने तथा गलत बिलों में सुधार की मांग करेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। किसानों का सवाल अब यही है कि यदि फ्लैट रेट योजना में बदलाव किया गया है तो उसका स्पष्ट आदेश क्या है और नैनपुर में लागू व्यवस्था का आधार क्या है?

आर्थिक सहायता स्वीकृत

मण्डला(स्वतंत्रमत)। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सर्पदंश से हुई एक महिला की असामयिक मृत्यु के प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत मृतक के निकटतम वारसान को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है ग्राम कोटासांगवा निवासी चैनवती मरावी की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी।

कार्यालय बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पिंडरई पं. क्र. 311

दिनांक-13 .09.2026

आमसभा सूचना पत्र

सम्मानीय महानुभाव, समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पिंडरई पं. क्र. 311 की साधारण वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2026 दिन मंगलवार को समय दोपहर 1 बजे से सामुदायिक भवन पिंडरई में आयोजित किया जाना है। गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में बैठक आधे घंटे स्थगित कर उसी दिन उसी स्थान पर होगी। जिसमें गणपूर्ति (कोरम) की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक में आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

विषय सूची निम्नानुसार है - 1. वर्ष 2025-26 में आयोजित की गई प्रबंधकारिणी बैठकों का अवलोकन / अनुमोदन बावद। 2. वर्ष 2025-26 की आय व्यय लाभ-हानि स्थिति विवरण का अनुमोदन बावद। 3. वर्ष 2026-27 में हुए व्ययों का अवलोकन एवं स्वीकृत बजट में से कम अधिक होने पर पुनरीक्षित समायोजन बावद। 4. वर्ष 2026-27 हेतु अनुमोदित बजट की स्वीकृती प्रदान करने बावद। 5. वर्ष 2024-25 के अडिट नोट का अनुमोदन करने बावद । 6. वर्ष 2026-27 के अंकेक्षण हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बावद । 7. अन्य विषय प्रशासक महोदय जी की अनुमति से।

प्रबंधक बहुउद्देशीय कृषि साख सह. समिति (बी पैक्स) पिंडरई पं.क्र.311

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील व जिला मंडला (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक: 0520/अ-6-अ/23-24

इश्तहार सार्वजनिक सूचना

यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 520/अ-6-अ/23-24 में आवेदक ललता प्रसाद साहू पिता हरिराम चाहू निवासी ग्राम ठरका, तहसील व जिला मंडला द्वारा ग्राम ठरका रा.नि.मं. बम्हनी स्थित भूमि ख.नं. 114 रकबा 0.35 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज है जिसके हस्तलिखित खसरा में संशोधित प्रविष्टि 20 में खसरा नं. 114/3 रकबा 0.02 हे. त्रुटि वश दर्ज किया जाकर अनावेदक प्यारी बाई एवं भारत लाल का नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे हटाया जाकर मूल ख.नं. 114 रकबा 0.35, हे. पर आवेदक का नाम दर्ज किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जाना अपेक्षित है इस हेतु यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है। उक्त सूचना ग्राम पंचायत ठरका के सूचना पटल पर चस्पा की जावे। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उक्त त्रुटि सुधार के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील व जिला मंडला के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता/सकती है। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रकरण में उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

पेशी दिनांक 23.09.26
स्थान:मंडला
दिनांक: 09/09/2026

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मण्डला

भारत-चीन संबंध, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन की चुनौती

भारत और चीन एशिया की दो प्रमुख शक्तियां हैं। बड़ी आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के कारण दोनों देशों के संबंध केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं हैं, बल्कि इनका असर पूरे एशिया और विश्व राजनीति पर पड़ता है। वर्तमान समय में भारत-चीन संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों दिखाई देते हैं। सीमा विवाद के कारण तनाव के बावजूद दोनों देश संवाद के रास्ते खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं।

सीमा विवाद, संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती

भारत और चीन के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के व्यापक संबंधों के लिए जरूरी है। सीमा पर तनाव कम करना और सैन्य स्तर पर संवाद बनाए रखना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। स्थिर सीमा संबंधों में विश्वास बढ़ाने की आधारशिला बन सकती है।

व्यापारिक संबंध, सहयोग के साथ असंतुलन

भारत और चीन के बीच व्यापार का आकार काफ ी बड़ा है। भारत चीन से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और कई औद्योगिक उत्पाद आयात करता है। वहीं भारत चीनी बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं की बेहतर पहुंच चाहता है। व्यापार घाटा भारत के लिए प्रमुख चिंता है। इसलिए भारत संतुलित व्यापार, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और बाजार तक बेहतर पहुंच पर जोर देता है।

बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग

दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय हैं। इन मंचों पर सहयोग विकासशील देशों की आवाज को मजबूत कर सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भारत की विदेश नीति को अधिक संतुलित और रणनीतिक बना दिया है।

भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि

भारत अमेरिका, जापान और अन्य देशों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाते हुए चीन के साथ भी संवाद और आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत की नीति का उद्देश्य किसी एक शक्ति के पक्ष में पूरी तरह झुकने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करना है।

संबंध सुधारने के लिए जरूरी कदम

भारत-चीन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सीमा पर शांति, निरंतर कूटनीतिक संवाद, संतुलित व्यापार और आपसी विश्वास जरूरी है। दोनों देशों के मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

वैश्विक राजनीति पर प्रभाव

भारत-चीन संबंधों को केवल मित्रता या विरोध के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। यह प्रतिस्पर्धा के साथ सह-अस्तित्व का संबंध है। दोनों देशों के फैसले एशिया के साथ-साथ वैश्विक शक्ति-संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए भारत के लिए चीन के साथ संबंधों में सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

स्नेहा जैन

शिक्षक
आदर्श हितकारिणी चिल्ड्रन एकेडमी, गोविंदगंज, जबलपुर

स्कूल की पाठशाला से जिम्मेदार नागरिक तक

स्कूल को अक्सर केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसकी भूमिका इससे कहीं अधिक व्यापक है। विद्यालय विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम, परीक्षा और अच्छे अंक हासिल करने के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि उनमें ऐसे संस्कार, मूल्य और जिम्मेदारियां विकसित करते हैं, जो उन्हें भविष्य का जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं।

किताबों से आगे जीवन की सीख

कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, लेकिन विद्यालय का वातावरण उन्हें जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रार्थना सभा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक गतिविधियां, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर देते हैं। इन गतिविधियों से उनमें अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित होती है।

तकनीक के दौर में मूल्यों की जरूरत

आज बच्चे तकनीक और सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। इंटरनेट ने सीखने के अवसर बढ़ाए हैं, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में विद्यालयों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विद्यार्थियों को तकनीक का सही और जिम्मेदार उपयोग करने के साथ ईमानदारी, संवेदनशीलता, सहनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों की सीख देना जरूरी है।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ

एक जिम्मेदार नागरिक केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझता है। विद्यालय विद्यार्थियों को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने, नियमों का पालन करने, दूसरों का सम्मान करने और जरूरतमंदों की सहायता करने जैसी जिम्मेदारियों से परिचित करा सकते हैं। यही छोटी-छोटी आदतें आगे चलकर मजबूत नागरिक चरित्र का निर्माण करती हैं।

शिक्षक और अभिभावक की साझी भूमिका

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक और अभिभावक दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चे केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के व्यवहार और अनुभवों से भी सीखते हैं। इसलिए घर और स्कूल के बीच सकारात्मक संवाद तथा मूल्यों में सामंजस्य बच्चों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है।

सफलता का अर्थ केवल अच्छे अंक नहीं

आज शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छा करियर हासिल करना नहीं हो सकता। एक सफल विद्यार्थी वह है, जिसके पास ज्ञान और कौशल के साथ समाज के प्रति संवेदनशीलता भी हो। विद्यालय यदि बच्चों को प्रश्न पूछने, सही निर्णय लेने, दूसरों का सम्मान करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें, तो वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकते हैं।

स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि

विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल अच्छे परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं का निर्माण है, जो अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार हों। ज्ञान के साथ संस्कार, अधिकारों के साथ कर्तव्य और सफलता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी ही शिक्षा को सार्थक बनाती है। यही विद्यालय की वास्तविक सामाजिक भूमिका और शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है।

प्रियंका पाठक खुरासिया

प्राचार्य
हितकारिणी कन्या उ.मा. शाला,
बीटी तिराहा, गढ़ा, जबलपुर।

क्या आप जानते हैं?

1 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।

2 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है।

3 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है।

4 भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा प्वाइंट है।

5 भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है।

6 भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंघा है।

7 भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है।

8 भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है।

9 भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है।

10 भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है।

जनता की भागीदारी से मजबूत होता है लोकतंत्र

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां लोकतंत्र केवल सरकार चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को अपने विचार रखने, सवाल पूछने और देश के विकास में भागीदारी का अवसर देता है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अधिकार दिए हैं। यही अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं।

लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनती है। चुनाव के जरिए नागरिक सरकार के कामकाज पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। यदि किसी सरकार का काम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, तो मतदाता अगली बार अपना निर्णय बदल सकते हैं। इस तरह जनता सरकार को जवाबदेह बनाए रखती है।

भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यह है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हैं।

भारत में अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचारधाराएं हैं। लोकतंत्र इन विविधताओं को स्थान देता है। अलग विचार रखने के बावजूद संवाद और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। देश के युवा लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शक्ति हैं। विद्यार्थियों को संविधान, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हासिल करनी चाहिए। जागरूक युवा ही भविष्य में जिम्मेदार मतदाता और नागरिक बन सकते हैं।

स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका, चुनाव व्यवस्था और नागरिक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही संस्थाएं सत्ता में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करती हैं।

वन और वन्यजीव बचेंगे, तभी पर्यावरण और जीवन सुरक्षित रहेगा

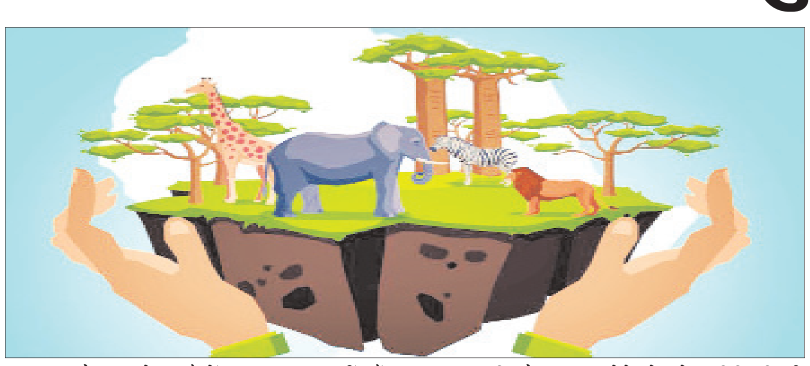

वन केवल पेड़-पौधों का समूह नहीं हैं, बल्कि असंख्य जीव-जंतुओं, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों का घर हैं। वे हवा को शुद्ध करने, वर्षा चक्र बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जलस्रोतों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वनों को प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है।

वन देते हैं स्वच्छ हवा और पानी

पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। वन वर्षा के पानी को जमीन में पहुंचाने और जलस्रोतों को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

वन्यजीव हैं प्रकृति की महत्वपूर्ण कड़ी

हर वन्यजीव की पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका होती है। शिकारी जीव शाकाहारी जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जबकि पक्षी और अन्य जीव बीजों के प्रसार में मदद करते हैं। किसी एक प्रजाति के समाप्त होने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन प्रभावित हो सकता है।

वनों के सामने बड़ी चुनौतियां

अवैध कटाई, बढ़ता शहरीकरण, खनन, जंगलों में आग और जलवायु परिवर्तन वनों के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। वन क्षेत्र कम होने से वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

विद्यार्थी बनें प्रकृति के प्रहरी

वन संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। विद्यार्थी पेड़ लगाकर और उनकी देखभाल करके, पानी बचाकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके तथा जंगलों में कचरा न फैलाकर योगदान दे सकते हैं। छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

जानिए जरूरी तथ्य

- वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद करते हैं।
- वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
- पेड़ों की जड़ें मृदा अपरदन रोकने में सहायक हैं।
- जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है।

परीक्षा में पूछे जा सकते हैं

1. वनों को प्रकृति का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है?

उत्तर- वनों को प्रकृति का सुरक्षा कवच इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हवा, पानी, मिट्टी और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों जरूरी हैं?

उत्तर- वन्यजीव खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

3. वनों के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन-सी हैं?

उत्तर- अवैध कटाई, शहरीकरण, खनन, वनाग्नि और जलवायु परिवर्तन प्रमुख चुनौतियां हैं।

करियर कनेक्शन

विद्यार्थी वन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वन्यजीव विज्ञान और पर्यावरण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। वन अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ इसके प्रमुख विकल्प हैं।

शब्द पहेली - 8976

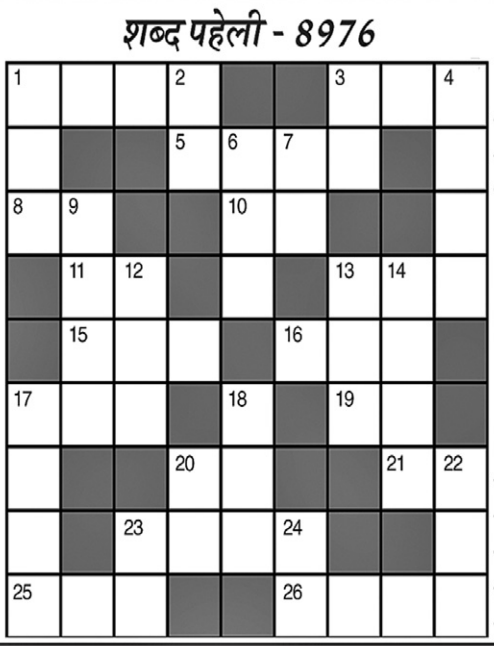

बाएँ से दाएँ

1. अँगरखा-4
3. मान-सम्मान, इज्जत-3
5. शुभाशीर्वाद, नियामत-4
8. केश-2
10. कसम, प्रतिज्ञा, वचन-2
11. बुरी आदत-2
13. मगरमच्छ-3
15. परिणाम-3
16. माँड़ी, स्टार्च-3
17. अक्षर (उर्दू-3)
19. रोम, केश-2
20. अधिकार, आरोप-2
21. सतह, स्तर, पटल-2
23. लूटपाट, डाका-4
25. सभ्यीकरण, विवेक-3
26. एक प्रसिद्ध कवि-4

ऊपर से नीचे

1. अनोखा, विचित्र, विलक्षण-3
2. नया, नवीन-2
3. इज्जत-2
4. कपोल-4
6. गमन, प्रेषित-3
7. पिता के पिता-2
9. चुनौती-4
13. गंदगी का ढ़ेर-3
14. असावधानी-4
17. जेल, कालकोठरी-4
18. शोर, ध्वनि, कंपन्न-3
20. ताप, शवदाह-2
22. यज्ञ, आहुति दान-3
23. रहस्य-2
24. जल, पानी-3

शब्द पहेली -8975 का हल

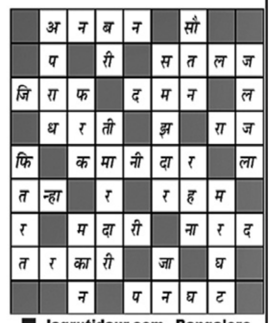

Jagrutidaur.com, Bangalore

Under the aegis of Hitkarini Sabha
Nurturing Excellence in Education Since 1868
HITKARINI
CHILDREN'S ACADEMY
PRIMARY | MIDDLE | HIGHER SECONDARY
English Medium Schools at Jabalpur

EXPERIENCED & DEDICATED FACULTY
Nurturing Young Minds
MODERN INFRASTRUCTURE
Learning with Innovation
FOCUS ON ACADEMICS, SPORTS, VALUES
Shaping Future Leaders

JONESGANJ
(Nursery to XII, Commerce)
Phone: 0761- 4129816
Website: www.kchca.hitkarini.edu.in

DIXITPURA
(Nursery to XII, Science / Commerce / Arts)
Phone: 0761-4129808
Website: www.bmd.hitkarini.edu.in

SAHAJPUR
(Nursery to VIII)
Mobile: 7389997882
Website: www.hcasahajpur.hitkarini.edu.in

DEVTAL, GARHA
(Nursery to VIII)
Phone: 0761- 4129814
Website: www.hgb.hitkarini.edu.in

GORAKHPUR
(Nursery to IX)
Phone: 0761- 4129812
Website: www.hssg.hitkarini.edu.in

GOVINDGANJ
(Nursery to XII, Science / Commerce)
Phone: 0761- 4129809
Website: www.hggs.hitkarini.edu.in

DUMNA ROAD
(Nursery to X)
Mobile: 9770277062
Website: www.hcadumna.hitkarini.edu.in

B.T. TIRAHA, GARHA
(Nursery to I)
Phone: 0761- 4129811
Website: www.hgg.hitkarini.edu.in

Head Office
Jonesganj, Jabalpur (M.P.) 0761-2410270, 2410578
www.hitkarini.com sabha@hitkarini.com
Scan to know more about us

संपादकीय

विश्वास से खिलवाड़

विशिष्ट खाद्य पदार्थ माने जाने वाले पनीर के नकलीपन को लेकर आजकल गहराता अविश्वास चिंता की बात है। मुनाफे के लिये उपभोक्ता के विश्वास से खिलवाड़ का यह धंधा पूरे देश में खूब चल रहा है। ये विडंबना ही है कि किसी उत्पाद की लागत, उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और ग्राहक को इस बाबत दी जाने वाली जानकारी में अकसर विरोधाभास पाया जाता है। देश में एनालॉग पनीर की धड़ल्ले से बिक्री के पीछे भी मुनाफे का प्रलोभन ही है। जिसमें वेजिटेबल फैट, स्टार्च, प्लांट प्रोटीन और गैर डेयरी उत्पादों को मिलाया जाता है। दरअसल, यह पनीर, असली दूध वाले पनीर की तुलना में काफी सस्ता होता है और उत्पादकों के मुनाफे को बढ़ाता है। जानकारों का अनुमान है कि कीमतों का यह अंतर चालीस से पचास फीसदी तक हो सकता है। ऐसे में जब रेस्टोरेंट, कैटरर और खाने-पीने के दूसरे कारोबार कम मुनाफे पर करते हैं तो महंगे पनीर के जगह सस्ता पनीर इस्तेमाल करने का लालच होना एक स्वाभाविक बात है। दरअसल, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हर एनालॉग प्रोडक्ट वास्तव में खाने की दृष्टि से असुरक्षित ही होता है। वास्तव में मुख्य समस्या धोखा देने की है। यदि किसी डेयरी पदार्थों से मुक्त विकल्प की पहचान स्पष्ट तौर पर एनालॉग पनीर के तौर पर की जाती है, तो ग्राहक सोच-समझकर उसको खरीदने के बारे में फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसको लेकर ईमानदारी न होना है। जब विक्रेता इसे दूध का पनीर बताकर बेचने लगते हैं तो उपभोक्ता निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में असली पनीर वाली पौष्टिकता उन्हें नहीं मिल पाती। निर्विवाद रूप से इस मामले में रेस्टोरेंट सबसे कमजोर कड़ी के रूप में सामने आते हैं। जिनका मुख्य मकसद अपने मुनाफे को प्राथमिकता देना ही होता है।

वास्तव में जब भी कोई रेस्टोरेंट अपने किचन में एनालॉग पनीर आदि का इस्तेमाल करना शुरू करता है और उससे कोई व्यंजन बना लेता है तो ग्राहक नहीं समझ पाता है कि असली पनीर है या नकली पनीर है। देश के खाद्य पदार्थों का नियमन करने वाली संस्था एफएसएसएआई ने फूड-सर्विस देने वाले संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि पनीर वाली डिश में एनालॉग पनीर का इस्तेमाल ग्राहकों को सही जानकारी दिए बिना न किया जाए। इस विवाद के चलते देश के कई राज्यों ने कृत्रिम पनीर के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार ने इसके बनाने, संग्रहण करने, ट्रांसपोर्ट करने, बांटने और पनीर के नाम पर बेचने पर एक साल के लिये रोक लगा दी है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि एनालॉग पनीर के खिलाफ छापेमारी और उस पर प्रतिबंध लगाने मात्र से यह समस्या हल नहीं होने वाली है। दरअसल, नियामकों को उन आर्थिक कारणों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से असली पनीर की जगह नकली पनीर का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। वास्तव में पनीर की जांच और गुणवत्ता के असली पनीर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही तमाम रेस्टोरेंट व होटलों को उन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिये जवाबदेह बनाना होगा, जिन्हें वे खरीदते हैं और ग्राहकों को परोसते हैं। बेशक, हर ग्राहक को इस बात का हक है कि वह जान सके कि वह किस तरह का पनीर खा रहा है। एनालॉग पनीर उत्पादकों को उत्पाद के पैकेट पर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होना चाहिए कि यह एनालॉग पनीर है। इसके अलावा सवाल इसके अर्थशास्त्र का भी है कि यदि उत्पादक इसके जरिये मुनाफा कमा रहे हैं तो उपभोक्ता को उस कीमत के अंतर का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही उन विक्रेताओं पर नकेल कसनी होगी जो असली पनीर की कीमत पर एनालॉग पनीर धड़ल्ले से बेच रहे हैं।

ब्रिक्स ने कर दी ग्लोबल साउथ की मजबूत दावेदारी

भाषा सिंह
अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार

भारत की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ ने विश्व राजनीति में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। दुनिया के 40 फीसदी से अधिक सकल घरेलू उत्पाद के मजबूत आधार वाले ब्रिक्स के 11 देशों ने सम्मेलन में आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों के साथ युद्ध, युद्ध जैसी स्थिति, टैरिफ वॉर, प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों पर बेहतर समझदारी विकसित की। बुनियादी तौर पर सहमति बनी कि ब्रिक्स देशों को एक-दूसरे पर आने वाले संकटों में साथ देना चाहिए। दिल्ली में 12-13 सितंबर को हुए इस शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की। छह महीने अमेरिका से जंग लड़ने के बाद भी उनके हौसले बुलंद हैं और वह मजबूती से ट्रंप राज के खिलाफ ताल ठोंकते नजर आए। भारत ने बतौर मेजबान कई देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों का भी आयोजन किया, जिसमें ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुलाकात बहुत अहम रही। ब्रिक्स 2026 का घोषणापत्र मौजूदा दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के मद्देनजर युद्ध के खिलाफ है और कहता है कि संघर्ष व जंग से नहीं, बल्कि बातचीत-आपसी सलाह से मसले हल किए जाने चाहिए। आतंकवाद की भर्त्सना के साथ-साथ तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों से बचने का प्रस्ताव लिया गया। टैरिफ वॉर से दुनिया पिछले एक साल से जूझ रही है। ब्रिक्स के देश खासतौर पर अमेरिका के टैरिफ वॉर के निशाने पर रहे हैं- चाहे चीन हो या भारत या फिर रूस और सभी के लिए इस टैरिफ के डंडे से बाहर निकलने का रास्ता खोजना प्राथमिकता थी। इस तरह 11-12-13 को ब्रिक्स के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा हुई। हालांकि घोषणापत्र में सीधे-सीधे अमेरिका का नाम नहीं है, लेकिन उसकी नीतियों के खिलाफ कई स्टेटमेंट हैं। मिसाल के तौर पर ईरान, रूस और चीन ने ब्रिक्स देशों के भीतर व्यापार कैसे स्थानीय मुद्रा में किया जा सकता है, इस पर सघन चर्चा की है। घोषणापत्र के निशाने पर इस्राइल है और खुलकर गाजा में हो रही हिंसा-बर्बरता के खिलाफ बोला गया है- जो अपने आप में ऐतिहासिक है। घोषणापत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स के देश तमाम पक्षों से यह आग्रह करते हैं कि वे गाजा में युद्धविराम का सम्मान करें। ब्रिक्स फलस्तीनियों को जबरन बाहर धकेलने के खिलाफ है और दो राष्ट्रों के निर्माण की अवधारणा के समर्थन में है। इस तरह से ब्रिक्स के तमाम देशों का फलस्तीन के पक्ष में आना और इस्राइल के खिलाफ बोलना एक मायने में अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ बोलना है। सारी दुनिया जानती है कि इस्राइल के फलस्तीन में हमले के पीछे अमेरिका है। ब्रिक्स 2026 का घोषणापत्र इस लिहाज से ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि इसके निशाने पर इस्राइल है और ईरान पर मंडरा रहे अमेरिकी युद्ध की लालसा है। अमेरिका का नाम लिए बिना पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव का जिक्र है और पश्चिमी एशिया में लगातार बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई गई है और कहा गया है कि ऐसे मामलों में तनाव कम करने के कदम उठाने चाहिए। अमेरिका के टैरिफ यानी तटकर के डंडे से ब्रिक्स के सभी देश परेशान नजर आए। चीन, रूस, ईरान, ब्राजील समेत इंडोनेशिया ने भी एकतरफा-मनमाने, तंग करने की नीयत से लगाए जाने वाले टैरिफ का विरोध

किया। भारत ने भी कहा कि इससे विश्व व्यापार प्रभावित होता है और सप्लाई चेन बाधित होती है। ब्रिक्स के 18वें सम्मेलन ने विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय व्यापार सिस्टम का समर्थन किया। इसमें तमाम देशों की साझेदारी संभव है। ये तमाम बातें निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को अखरेंगी, क्योंकि हर मोर्चे पर उनके एजेंडे को चुनौती दी जा रही है। दुनिया को यूनिपोलर यानी एकध्रुवीय बनाने के ट्रंप के सपने को इस सम्मेलन में कड़ी चुनौती मिली है। इसमें बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ ईरान और उसका कूटनीतिक दांव। जिस तरह से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन में अपने एजेंडे को आगे रखा और अमेरिका के खिलाफ चल रहे अपने छह महीने के संघर्ष को खुलकर रखा और यह ऐलान किया कि ईरान को गुलाम बनाना असंभव है। उनकी बातों ने माहौल बना दिया। अमेरिका ने जैसे ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया- उसे भी राष्ट्रपति मसूद ने एक मुद्दा बनाया और कहा कि दरअसल ब्रिक्स के देशों को इनके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा है। मसूद ने साथ में फलस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में अहम बिंदु रखा कि इसके पक्ष में बात करके ही दरअसल ग्लोबल गवर्नेंस की साख की परीक्षा हो सकती है। उधर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप व अमेरिका के खिलाफ जमकर बैटिंग की। पुतिन ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि रूस सबका दोस्त है और वे यूरोप को सस्ते में तेल बेच रहे थे- 150 डॉलर प्रति 1,000 क्यूबिक मीटर और अब वे 1,000 डॉलर दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों में 1,500 डॉलर हो सकता है। पुतिन ने विकसित देशों के समूह जी-7 की आलोचना करते हुए कहा कि भविष्य ब्रिक्स का है, जीडीपी, आबादी और बाजार के लिहाज से। अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पष्ट रेखा खींचने का काम किया और कहा कि युद्ध बेकार की चीज है, इससे आम नागरिक का भला नहीं होता। हमें युद्ध के नहीं, शांति, सहयोग, वार्ता और व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान रखना होगा। ब्रिक्स को इतिहास के सही पक्ष में खड़ा होना है और सारे देश इसके लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संतुलित रुख अख्तियार करने की कोशिश की गई। दरअसल, ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए ग्लोबल साउथ देशों की वर्ल्ड ऑर्डर में हिस्सेदारी तय करने का काम किया गया। ये एक बेहद जरूरी हस्तक्षेप है। इस साल ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की थीम थी- 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण', जो युद्ध और बढ़ते तनाव के माहौल में अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। ब्रिक्स के देश 370 करोड़ लोगों की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी मांग को अनसुना करना इस समय संभव नहीं है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का एक ऐसा अंतर-सरकारी मंच है, जिसमें लगातार विस्तार हो रहा है। जनवरी, 2024 में इसमें इज़िप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को शामिल किया गया। फिर जनवरी, 2025 में इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हुआ। इस तरह से ब्रिक्स दुनिया के 11 अहम उभरते बाजारों व विकासशील देशों को एकसाथ ला रहा है। दिल्ली में हुए इस 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में उसके घोषणापत्र में विकास की बहुरंगी छाप की आस दिखी है, बाजार और तकनीक में समन्वय की गुंजाइश दिखती है।

आरक्षण पर नई बहस

हक किसका, अवसर किसे?

प्रीति गुप्ता
समाजसेवी

भारत में आरक्षण केवल एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, सामाजिक असमानता और समान अवसर की लंबी यात्रा से जुड़ा विषय है। इसलिए आरक्षण पर बात करते समय न तो भावनाओं को भड़काना उचित है और न ही वास्तविक सामाजिक वंचना को नकारना। लेकिन आज समय की मांग है कि हम एक कठिन सवाल पूछें- क्या आरक्षण की व्यवस्था को बदलते भारत के अनुसार समय-समय पर समीक्षा और सुधार की आवश्यकता नहीं है? आरक्षण का मूल उद्देश्य उन लोगों को अवसर देना था जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँचे। आज हमें यह भी देखना होगा कि एक ही श्रेणी में आने वाले सभी परिवारों की परिस्थितियाँ समान नहीं हैं। किसी परिवार के पास वर्षों से अच्छी शिक्षा, आर्थिक स्थिरता और सरकारी सुविधाओं तक पहुँच है, जबकि उसी श्रेणी का दूसरा परिवार आज भी गरीबी, कमजोर शिक्षा और अवसरों की कमी से जूझ रहा है। तो क्या दोनों की जरूरत एक जैसी मानी जानी चाहिए? यहीं से आरक्षण व्यवस्था में अधिक सूक्ष्म और पारदर्शी सुधार की आवश्यकता सामने आती है।

जरूरतमंद तक पहुँचे लाभ

आरक्षण की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामाजिक पिछड़ेपन के साथ-साथ परिवार की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक अवसर और पीढ़ीगत वंचना जैसे पहलुओं पर भी गंभीर विचार हो। जहाँ लागू हो, क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों को प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक गरीब परिवार का बच्चा चाहे किसी भी सामाजिक वर्ग से आता हो, यदि उसके पास गुणवत्तापूर्ण स्कूल, कोचिंग, इंटरनेट, किताबें और आर्थिक संसाधन नहीं हैं तो उसके लिए प्रतियोगिता कठिन है। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए- गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा, छात्रवृत्ति, नि:शुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, हॉस्टल और डिजिटल सुविधाएँ, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

समान तैयारी का अवसर चाहिए

सच्चा समान अवसर केवल परीक्षा में बराबर प्रश्नपत्र देने से नहीं आता। समान अवसर तब आएगा जब गाँव के बच्चे और महानगर के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तैयारी के समान साधन मिलेंगे। इसलिए हमें आरक्षण के साथ शिक्षा सुधार पर भी उतनी ही गंभीरता से बात करनी होगी। कोई भी नीति समाज की बदलती परिस्थितियों से अलग नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण से जुड़े आँकड़ों, लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और वास्तविक परिणामों का नियमित, पारदर्शी और स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि आरक्षण किसके खिलाफ है।सवाल होना चाहिए- आरक्षण किसे वास्तव में आगे बढ़ा रहा है और जो सबसे पीछे है, वह अब भी पीछे क्यों है?

लक्ष्य क्या होना चाहिए?

हमारा लक्ष्य ऐसा भारत होना चाहिए जहाँ जन्म किसी व्यक्ति की सफलता तय न करे। जहाँ ऐतिहासिक रूप से वंचित व्यक्ति को न्याय मिले। जहाँ गरीब विद्यार्थी को अवसर मिले। जहाँ प्रतिभा को मंच मिले। और जहाँ किसी युवा को यह महसूस न हो कि उसके सपनों की सीमा उसके जन्म से तय हो गई है। आरक्षण पर बहस होनी चाहिए-लेकिन नफरत के साथ नहीं, तथ्यों के साथ। सुधार की मांग होनी चाहिए- लेकिन किसी समुदाय को अपमानित किए बिना। और सबसे महत्वपूर्ण- हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें सामाजिक न्याय भी सुरक्षित रहे और समान अवसर भी मजबूत हो। आरक्षण की बहस का अंतिम लक्ष्य किसी को हटाना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना होना चाहिए जहाँ एक दिन हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए समान और सम्मानजनक अवसर मिले।

गणेश जी से सीखें अपनी सीमा को ताकत बनाना

डॉ. रेणु सैनी

हमारी भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का सर्वप्रथम स्मरण करने और उन्हें आमंत्रित करने से कार्य में विघ्न नहीं आते तथा सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। गणेश जी आज की युवा पीढ़ी के लिए ऐसे प्रबंधन गुरु हैं, जो अपने व्यक्तित्व और गुणों से यह बताते हैं कि बुद्धि, विवेक और चातुर्य सब पर भारी पड़ता है। बेडौल व्यक्तित्व भी गुणों के आगे मिसाल बन जाता है।

आजकल अधिकतर युवा संसाधनों और व्यक्तित्व की छोटी-बड़ी कमियों के कारण तनावग्रस्त हो रहे हैं और कई बार घातक कदम तक उठा लेते हैं। उनके भीतर निराशा इस कदर छा जाती है कि वे उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। यदि वे निराशा के भंवर से बाहर निकलकर देखें, तो समझ पाएंगे कि देवताओं ने भी अनेक बाधाओं को पार किया था। बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करने के कारण ही वे देव कहलाए। जीवन में कुछ भी सहजता से नहीं मिलता। जो सरलता से मिल जाता है, उसमें वह आनंद नहीं आता, जो संघर्ष के बाद प्राप्त वस्तु में मिलता है। संघर्ष के साथ-साथ व्यक्ति के भीतर विवेक और बुद्धि का होना भी अनिवार्य है। कई बार जो कार्य बल से नहीं होते, वे बुद्धि से संपन्न हो जाते हैं। गणेश जी ने अनेक अवसरों पर अपने कार्यों से सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान चमत्कार से नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि से होता है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अनुशासन, अनुकूलन और समय प्रबंधन ही सफलता की नींव तैयार करते हैं।

अक्सर युवा शिकायत करते हैं कि उनके पास सीमित संसाधन थे, इसलिए वे परीक्षा अथवा नौकरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। गणेश जी को जब प्रथम पूज्य बनने की चुनौती दी गई और कहा गया कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी, तब उन्होंने अपने धीमे

वाहन मूषक को लेकर कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी सीमा को ही ताकत बना लिया। गणेश जी ने मूषक के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की तीन बार परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए माता-पिता ही पूरे ब्रह्मांड से बढ़कर हैं। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर सभी ने उन्हें प्रथम पूज्य स्वीकार कर लिया। जब गणेश जी महाकाव्य लिख रहे थे, तब अचानक उनकी कलम टूट गई। उन्होंने न तो कलम टूटने का बहाना बनाया और न ही लेखन कार्य रोका। उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम की तरह प्रयोग करके महाकाव्य लिखना जारी रखा। इसी त्याग के कारण उनका नाम 'एकदंत' पड़ा। यदि ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए, तो हममें से अनेक लोग समस्या का समाधान खोजने के बजाय समय बर्बाद करने लगेंगे। आजकल कई युवा जीतने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और कभी-कभी षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकते। इसके विपरीत, गणेश जी ने एक बार अपने बड़े भाई कार्तिकेय के सम्मान और भाईचारे के लिए जान-बूझकर हार स्वीकार की। माता पार्वती ने जब इसका कारण पूछा, तो उन्होंने सहज भाव से कहा, 'जहां अपनों का सम्मान और भाईचारा दांव पर लगा हो, वहां जीतकर भी हार हो जाती है। संबंधों की मिठास हर जीत से बड़ी होती है।' यह विचार आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है। गणेश जी के आंतरिक गुणों के अतिरिक्त उनका बाहरी व्यक्तित्व भी प्रबंधन का अद्भुत पाठ पढ़ाता है। उनका मस्तक अत्यंत विशाल है, जो प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति को बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है। बड़ी सोच दूरदर्शिता का परिचायक होती है और व्यक्ति को अनेक संकटों से बचाती है। उनके छोटे नेत्र जीवन में लक्ष्य के प्रति सूक्ष्म दृष्टि रखने की सीख देते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से व्यक्ति अपने निर्णयों को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बना सकता है।

गणेश जी के कान बहुत बड़े और मुख छोटा है। उनके ये दोनों अंग प्रत्येक व्यक्ति को कम बोलने और अधिक सुनने की प्रेरणा देते हैं। आज अधिकतर लोग दूसरों को सुनाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब दूसरों की सुनने की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। दूसरों की बातें सुनने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, जबकि अपनी ही धुन में बोलते रहने से ज्ञान सीमित रह जाता है। सुनना किसी जादू से कम नहीं है। जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स के अनुसार, 'दूसरों की बातें सुनना ही वह सबसे असरदार तरीका है, जिससे कोई व्यक्ति संसार में लोगों को साथ लेकर चल सकता है और उन्हें अपना मित्र बना सकता है।' गणेश जी का संपूर्ण व्यक्तित्व जीवन प्रबंधन का ऐसा सूत्र है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति सुख, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, समृद्धि और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है।

चेक बाउंस विवादों में तकनीक बने समाधान

डॉ. सुधीर कुमार
सहायक प्रोफेसर
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

देश की अदालतों में करोड़ों लंबित मामलों में से एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 यानी चेक बाउंस के मामलों की है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक, चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इनमें से अधिकांश विवाद वित्तीय लेन-देन से जुड़े असंतोष या छोटी-मोटी चूकों के कारण होते हैं। इसके बावजूद, एक साधारण-सा चेक बाउंस होने पर कानूनी नोटिस भेजने से लेकर अदालत में समन जारी होने, गवाही, जिरह और फैसले तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मामलों में माना है कि इन मुकदमों का अंतहीन चलना व्यापारिक जगत और न्यायपालिका, दोनों के लिए घातक है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण और लैंडमार्क फैसले हैं। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लिए गए मामले 'इन री: एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेज अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, 1881 (2020)' में बड़ी बेंच ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई थी कि देश की अदालतों में चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं और इनका अंतहीन चलना न्याय व्यवस्था व व्यापारिक माहौल, दोनों के लिए घातक है।

इसके साथ ही, 'दशरत रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र' (2014) के ऐतिहासिक मामले में भी न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि पारंपरिक मुकदमेबाजी में वादी और प्रतिवादी, दोनों का धन, समय और मानसिक सुकून नष्ट होता है। न्यायालयों ने कई बार मध्यस्थता और त्वरित न्याय प्रणालियों पर जोर दिया है, क्योंकि जिस मामले को बैंक स्तर पर या चंद दिनों में सुलझाया जा सकता है, उसे वर्षों तक कचहरी के चक्कर कटवाए जाते हैं। इस स्थिति में हमें लीक से हटकर सोचना होगा और एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल अपनाना होगा, जो पूरी तरह तकनीक पर आधारित हो। यहां एक अनूठा और आधुनिक तरीका काम आ सकता है- 'स्मार्ट-ब्रीच ऑटो-रेज़ोल्यूशन पोर्टल'। कल्पना कीजिए कि जैसे ही किसी व्यक्ति का चेक बैंक में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस होता है, पारंपरिक कागजी प्रक्रिया शुरू होने के बजाय एक स्वचालित डिजिटल ट्रिगर सक्रिय हो जाए। इस नए मॉडल के तहत, बैंक स्तर पर ही

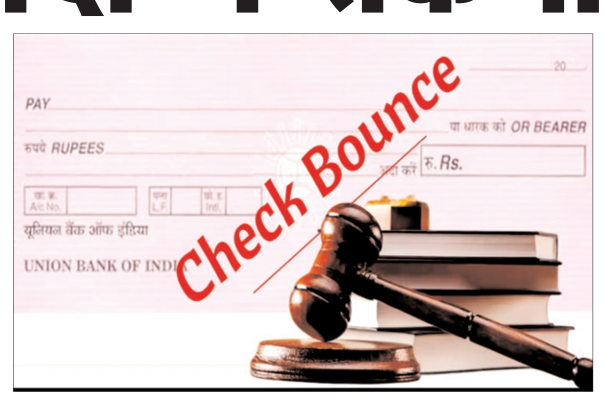

एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर काम करे, जो तुरंत संबंधित व्यक्ति के खाते से एक निश्चित डिजिटल पेनल्टी और मूल राशि का आंशिक या पूर्ण ट्रांसफर सुनिश्चित करे; बशर्ते दोनों पक्षों के बीच पहले से डिजिटल एग्रीमेंट हो। यदि राशि को लेकर विवाद है, तो मामला सीधे कोर्ट जाने के बजाय ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म पर डायवर्ट हो जाए। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा वर्चुअल कोर्ट रूम या मध्यस्थता मंच है, जहां कोई वकील, कोई तारीख और कोई कागजी फाइल नहीं होती। दोनों पक्ष घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए अपने दस्तावेज अपलोड करते हैं। एक प्रशिक्षित एआई-असिस्टेड मीडिएटर या डिजिटल एल्गोरिद्म दोनों पक्षों के डिजिटल रिकॉर्ड को खंगालकर 7 से 15 दिनों के भीतर एक बाध्यकारी समझौता प्रस्ताव तैयार कर देता है। यदि कोई पक्ष इसका उल्लंघन करता है, तो उसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल स्कोर स्वत: डाउन हो जाता है और उसके अन्य बैंक खातों पर स्वचालित डिजिटल होल्ड लग जाता है। यह तरीका न केवल अदालतों का बोझ कम करेगा, बल्कि आम आदमी को मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाएगा। डिजिटल न्याय प्रणाली की सफलता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समझ, इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी जैसी व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

ग्राम स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से डिजिटल हेल्प डेस्क बनाए जाने चाहिए, ताकि मुफ्त या कम शुल्क में तकनीकी सहायता मिल सके। जब तक डिजिटल साक्षरता और समावेशी मॉडल विकसित नहीं होंगे, तब तक न्याय का स्थानीयकरण अधूरा रहेगा। कानूनी ढांचे में दूरगामी बदलाव करते हुए सबसे पहले चेक बाउंस जैसे मामलों में प्री-लिटिगेशन मेडिएशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे बैंक खाते से संदेश आते ही 15 दिनों की ऑनलाइन बातचीत के जरिए आधे से अधिक मामले अदालत पहुंचने से पहले ही सुलझ सकें। इसके साथ ही, कंपाउंडिंग यानी समझौते के नियमों का स्वत: क्रियान्वयन लागू होना चाहिए, ताकि आरोपी द्वारा डिजिटल माध्यम से मूल राशि व हर्जाना जमा करते ही, बिना अदालती चक्कर और जज की अनुमति के, मामला स्वत: समाप्त होकर सिस्टम से केस क्लोजर रिपोर्ट जारी हो सके। चेक बाउंस के मामलों में लोग जेल जाने के डर से भागते फिरते हैं या कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर वर्षों तक तारीखें लेते रहते हैं। हमें जेल भेजने की पुरानी ब्रिटिशकालीन मानसिकता से बाहर निकलकर कड़े वित्तीय दंड और दीर्घकालिक सिबिल पाबंदियों को सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। जानबूझकर चेक बाउंस करने वालों पर चेक राशि का 3 से 5 गुना भारी जुर्माना लगाया जाए, जो सीधे पीड़ित को मिले, और उनका सिबिल स्कोर इतना गिरा दिया जाए कि वे अगले 5 वर्षों तक नया लोन या क्रेडिट कार्ड न पा सकें। जब व्यक्ति के वित्तीय जीवन पर सीधा प्रहार होगा, तो वह अदालती चक्कर काटने के बजाय समय पर भुगतान करना खुद-ब-खुद सीख जाएगा। जब तक हम प्री-लिटिगेशन मेडिएशन, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और डिजिटल ऑटोमेशन को न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक तारीखों के इस जंजाल से राहत नहीं मिल सकती।

गुरुद्वारे के पीछे रेलवे परिसर में कचरा फेंका तो लगेगा जुर्माना

कई साल से बनी गंदगी की समस्या पर नगर पालिका ने कसी नकेल

करेली (स्वतंत्र मत)। रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों और आगंतुकों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बने गुरुद्वारे के पीछे रेलवे परिसर में फैली गंदगी की समस्या पर अब नगर पालिका परिषद करेली ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कई वर्षों से आसपास के दुकानदारों और रहवासियों द्वारा यहां लगातार कचरा फेंके जाने से पूरा क्षेत्र गंदगी की चपेट में था। स्टेशन की ओर आने वाले लोगों को भी यहां फैली गंदगी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कई बार दुकानदारों और रहवासियों को समझाइश देकर सार्वजनिक स्थान पर कचरा नहीं फेंकने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए नगर पालिका द्वारा मौके पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कराई गई, ताकि दुकानदार और रहवासी अपना कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग करने के बजाय आसपास कचरा फेंकने का सिलसिला जारी रखा गया।

24 घंटे कैमरे से निगरानी

लगातार समझाइश और वैकल्पिक व्यवस्था के बाद भी गंदगी फैलाए जाने को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका ने अब मौके पर अपना अमला तैनात कर दिया है। नगर पालिका के कर्मचारी 24 घंटे क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए कैमरा भी लगाया गया है, जिससे सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

गंदगी फैलाने पर 1000 का जुर्माना

निगरानी के दौरान गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर पालिका द्वारा 1000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। यदि कोई दुकानदार या रहवासी रेलवे परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

स्वच्छता में नागरिकों की सहभागिता जरूरी

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार के मार्गदर्शन में नगर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर पालिका की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि आने-जाने वाले लोगों के बीच भी गलत संदेश जाता है।

सीएमओ ने दिए सख्ती के निर्देश

नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर के निर्देशन में रेलवे परिसर सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर नजर रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाए।

कचरा गाड़ी में ही दें गीला-सूखा कचरा

नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में नियमित रूप से कचरा संग्रहण वाहन भेजे जा रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घर और दुकानों का कचरा सड़क, नाली, खाली प्लॉट अथवा सार्वजनिक स्थान पर न फेंकें। कचरा नगर पालिका की कचरा गाड़ी में ही दें और गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग करके दें। नगर पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गुरुद्वारे के पीछे रेलवे परिसर सहित नगर में कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ और सुंदर करेली के लिए नागरिक नगर पालिका का सहयोग करें।

कान्हीवाड़ा और बरघाट में जनविश्वास की मिसाल बने मोहनीश बैस, अब छिंदवाड़ा में संभालेंगे नई जिम्मेदारी

सिवनी (स्वतंत्र मत)। पुलिस विभाग में अधिकारियों का स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें जनता लंबे समय तक याद रखती है। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा एवं बरघाट थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी के रूप में सेवाएं देने वाले मोहनीश बैस भी ऐसे ही अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कार्यशैली, कर्तव्यनिष्ठा और सहज व्यवहार से आमजन के बीच अलग पहचान बनाई।

मोहनीश बैस की पुलिसिंग में अपराधियों के प्रति कानून के अनुरूप सख्ती और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता देखने को मिली। उनकी मृदु वाणी, सरल स्वभाव तथा जनसामान्य से आत्मीय व्यवहार के कारण दोनों थाना क्षेत्रों में उन्होंने जनविश्वास अर्जित किया। उनके कार्यकाल को क्षेत्र की जनता एक ऐसे दौर के रूप में याद करेगी, जब पुलिस की वर्दी में अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता का बेहतर समन्वय देखने को मिला।

अब मोहनीश बैस अपनी सेवाएं छिंदवाड़ा जिले में प्रदान करने जा रहे हैं। उनके स्थानांतरण से छिंदवाड़ा को एक कर्मठ एवं व्यवहारकुशल पुलिस अधिकारी की सेवाएं मिलेंगी, वहीं सिवनी जिले में उनके साथ जुड़े लोगों और आमजन के लिए यह आत्मीय विदाई का अवसर है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि अच्छे अधिकारी का तबादला केवल कार्यक्षेत्र बदलता है, उनकी कर्मठता, व्यवहार और कार्यों की स्मृतियां नहीं। मोहनीश बैस ने अपने कार्यकाल के दौरान जो विश्वास अर्जित किया, वह उनके स्थानांतरण के बाद भी लोगों के बीच बना रहेगा।सिवनीवासियों की यही शुभकामना है कि वे अपने नए कार्यक्षेत्र में भी इसी निष्ठा और समर्पण के साथ पुलिस विभाग की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। साथ ही भविष्य में वे अनुविभागीय अधिकारी के रूप में पुन: सिवनी जिले में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त करें, ऐसी मंगलकामना भी क्षेत्रवासियों ने व्यक्त की है।ऐसे कर्मठ और जनप्रिय पुलिस अधिकारी को सिवनी की जनता की ओर से आत्मीय शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को रक्तदान शिविर

सिवनी (स्वतंत्र मत)। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला सिवनी द्वारा 17 सितंबर 2026, गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन भाजपा कार्यालय, सिवनी में प्रात: 11 बजे से किया जाएगा। रक्तदान शिविर के माध्यम से युवाओं एवं आम नागरिकों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए मानवता की सेवा में योगदान देने का आह्वान किया गया है। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्य को लेकर अधिक से अधिक लोगों से शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की गई है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, जिला सिवनी शुभम राजपूत ने नागरिकों से रक्तदान शिविर में सहभागी बनने का आग्रह किया है।

जिला चिकित्सालय पहुंचकर असलम बाबा ने दिया स्वच्छता का संदेश

सिवनी (स्वतंत्र मत)। जिला चिकित्सालय द्वारा अधिकृत सामाजिक संस्था कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष असलम बाबा ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के बच्चा वार्ड चिल्ड्रन वार्ड पहुंच कर मरीज के परिजनों को स्वच्छता का संदेश दिया और अपील की बच्चों में बुखार सर्दी की बहुत की शिकायती आ रही है। और बच्चे बीमार हो रहे हैं।बीमारी से बचने के लिए हमें हमारे आसपास स्वच्छता बनाए रखना है। जिससे हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहें। जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजन को बताया गया सभी परिजनों ने ध्यानपूर्वक असलम बाबा की बात सुनी और सहयोग करने के लिए कहा। जिला चिकित्सालय आपका अपना है।यहां पर आपको स्वच्छता बनाए रखनी है । जिससे जल्द से जल्द आपका बच्चा स्वस्थ होकर घर जाए इसके लिए सबसे जरूरी है स्वच्छता बनाए रखना। जिला चिकित्सालय मे सभी परिजन को सहयोग भी करना है। जिससे हमारा जिला चिकित्सालय साफ स्वच्छ बना रहे। चिल्ड्रन वार्ड में साफ सफाई बहुत अच्छे से कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। उपस्थित रहा चिल्ड्रन वार्ड का स्टाफ।

मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की

सिवनी (स्वतंत्र मत)। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान को केवल आयोजन तक सीमित न रखते हुए इसे जनभागीदारी, सेवा और जनकल्याण से जोड़ते हुए प्रभावी एवं यादगार बनाया जाए। उन्होंने जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों तक अभियान की गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक नागरिकों को सहभागी बनाने के निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के माध्यम से होगी। शाम 7 बजे जिले के चिन्हित स्थलों सहित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में एक साथ दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में नागरिकों, लाभार्थी परिवारों, सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य संगठनों को जोडने् तथा आयोजन स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अभियान के तहत जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ब्लड बैंक, रेडक्रॉस एवं मेडिकल कॉलेज के साथ समन्वय कर चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक नागरिकों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विद्यार्थियों की सहभागिता पर भी विशेष जोर दिया गया। 'मेरे सपनों का भारत' चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता में जिले के सरकारी एवं निजी स्कूलों तथा कॉलेजों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों को अपने विचारों एवं कल्पनाओं को चित्र और भाषण के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। विजेता विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिले में श्रेष्ठ चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी तथा प्रतिभागी संस्थानों, विद्यार्थियों एवं चित्रों के विषय का विवरण व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाएगा।'नमो सेवा-अनकही कहानियां' के माध्यम से भी जिले में सेवा और समर्पण की प्रेरणादायी कहानियां आमजन तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 10 नुक्कड़ नाटक दल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सिवनी में इन दलों का पूर्वाभ्यास कराते हुए हाट-बाजार, मुख्य बाजार, कॉलोनी एवं बस्तियों जैसे स्थानों पर प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। उत्कृष्ट नाट्य दलों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा।

'आंगन मिलन सेवा' के अंतर्गत जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। यहां बच्चों और माताओं के लिए पोषक स्वल्पाहार, फल एवं मिठाई, खेल सामग्री, रुचिकर पुस्तकें एवं अन्य बाल-सुलभ सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री की अपील का वीडियो मोबाइल अथवा टीवी के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को दिखाया जाएगा। बच्चों, माताओं एवं अभिभावकों से जीवंत संवाद के साथ स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए कार्यक्रम की तिथि एवं नोडल अधिकारी का निर्धारण किया जाएगा।समीक्षा के दौरान 'सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार' की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड स्तर पर तथा नगरीय निकायों में जोनवार मेगा शिविर आयोजित कर केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। शिविरों में आवेदनों के पंजीयन से लेकर निराकरण और हितलाभ वितरण तक की जानकारी व्यवस्थित रूप से संधारित की जाएगी। 'जन-विश्वास अभियान' को भी सेवा सेतु के साथ जोडक़र आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने और योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि सेवा संकल्प अभियान की प्रत्येक गतिविधि में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो और कार्यक्रमों का प्रभाव गांव से लेकर शहर तक दिखाई दे। उन्होंने सभी आयोजनों की पूर्व तैयारी, स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार, आवश्यक व्यवस्थाओं तथा कार्यक्रमों के व्यवस्थित अभिलेखीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला कांग्रेस कमेटी नरसिंहपुर की अति महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

नरसिंहपुर ।स्वतंत्रमत। जिला कांग्रेस कमेटी, नरसिंहपुर की अति महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आज जिला कांग्रेस कार्यालय, मुशरान भवन, नरसिंहपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पटेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों तथा जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर-बैठक में आगामी 19 सितंबर 2026 को इंदौर में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिले की सहभागिता, कार्यकर्ताओं की भागीदारी, संगठनात्मक समन्वय तथा विभिन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पटेल जी ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी निष्ठा, समर्पण और सक्रियता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन की एकजुटता को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। नवीन दायित्वों की जानकारी एवं संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान बैठक में कांग्रेस संगठन प्रभारी दीवान शैलेंद्र सिंह जी ने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को उनके नवीन संगठनात्मक दायित्वों की जानकारी दी।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक अनुशासन एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन की मजबूती प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के साथ-साथ जिले के प्रत्येक गांव, नगर एवं बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए सभी को मिल-जुलकर कार्य करना होगा।बैठक में उपस्थित कांग्रेसजनों ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने तथा पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूरी सक्रियता एवं एकजुटता के साथ कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

महिलाओं ने किया हरितालिका तीज की पूजन सामग्री का विसर्जन

सिवनी (स्वतंत्र मत)। हरितालिका तीज के अवसर पर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं ने विधि-विधान से भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा-अर्चना के बाद मंगलवार को प्रात: करीब 6 बजे से पूजन सामग्री एवं शिव-पार्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू किया।

इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धा के साथ विसर्जन स्थलों पर पहुंचीं।महिलाओं ने पूजा-अर्चना के बाद परिवार की सुख-समृद्धि, पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की कामना की। सुबह से ही विसर्जन स्थलों पर महिलाओं की आवाजाही बनी रही। महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा सामग्री का विसर्जन कर व्रत की धार्मिक प्रक्रिया पूर्ण की।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर लक्ष्य पूर्ति में तेजी लाने के दिए निर्देश

डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की समीक्षा बैठक सम्पन्न

नरसिंहपुर। स्वतंत्रमत। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ श्री अंकुश सिन्हा, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) श्री विकास पवार, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा जिले में संचालित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे। बैठक में जिले में बैंकिंग गतिविधियों एवं शासकीय योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जा रही ऋण सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जून 2026 तक के जमा-साख अनुपात, वार्षिक साख योजना, बैंकवार एवं क्षेत्रवार अग्रिम की उपलब्धि तथा जिले में एनपीए की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बैंकवार प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों, पशुपालन, मत्स्य, जनजातीय कार्य, अंत्यावसायी एवं उद्यानिकी विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

सेवा संकल्प अभियान के जरिए जन-जन तक पहुंचेगा सेवा और विकास का संदेश

सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता

नरसिंहपुर ।स्वतंत्रमत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा को जन-जन तक पहुंचाने तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान की संपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए भाजपा कार्यालय में मुख्य वक्ता श्रीमती माया नारोलिया राज्यसभा सांसद, रामस्नेही पाठक जिला भाजपा अध्यक्ष, विश्वनाथ सिंह पटेल विधायक तेंदूखेडा ज्योति काकोड़िया जिला पंचायत अध्यक्ष, सुरेंद्र मोहन नेमा जिला महामंत्री, राहुल कौरव जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल पूर्व जिला महामंत्री, वैभव नेमा विधायक मीडिया प्रभारी की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर रक्तदान शिविर सहित विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश के सभी बूथों पर शाम 7 बजे 'आशीर्वाद का दिया' कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को प्रदेशभर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।अभियान के तहत 'नमो सेवा-अनकही कहानियां' के माध्यम से प्रधानमंत्री के जनकल्याणकारी कार्यों और योजनाओं से आए बदलावों को नुक्कड नाटक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं

'आंगन मिलन सेवा' के तहत आंगनबाडी केंद्रों में बच्चों और उनकी माताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित कर पोषण, स्वास्थ्य एवं विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी इसके साथ ही बताया कि प्रदेश के सभी 11,404 शक्ति केंद्रों पर 'सेवा की कहानी' कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नागरिकों की वास्तविक सफलता की कहानियां सामने लाई जाएंगी। प्रत्येक शक्ति केंद्र से कम से कम 10 कहानियां तैयार कर सोशल मीडिया पर साझा की जाएंगी।'सेवा ज्योति कलश यात्रा-विकसित भारत का संकल्प' के तहत 7 अक्टूबर को विभिन्न गांवों और क्षेत्रों को जोडते हुए पदयात्रा, साइकिल रैली और बाइक रैली आयोजित होंगी। यात्रा के समापन पर सामूहिक रूप से विकसित भारत-2047 का संकल्प लिया जाएगा। वहीं 'नर्मदा यात्रा' के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जल लेकर वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा अभियान में 'सेवा मेरा योगदान' के तहत प्रत्येक कार्यकर्ता समाजसेवा में अपना योगदान देगा। नागरिक भी श्रमदान कर अभियान में सहभागिता कर सकेंगे। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों में 'सेवा सेतु अभियान' के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने तथा योजनाओं से संबंधित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया में सहायता की जाएगी।अभियान के अंतर्गत 'सेवा के रंग राष्ट्र के संग', 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' सहित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। युवाओं, विद्यार्थियों, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को जोडकर नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा उक्त जानकारी देते हुए विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक ने सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा भावना, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत-2047 के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों को विकसित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में सहभागी बनाया जाएगा।

मानवता अभी जिंदा है घायल नंदी बछड़े को मिला नया जीवन

शहडोल (स्वतंत्रमत)। अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल था नंदी, गौसेवकों और जेसीबी चालक ने मिलकर किया सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाणगंगा मैदान में अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे पड़े एक नंदी बछड़े के लिए गौसेवक फरिश्ता बनकर पहुंचे। स्थानीय लोगों की सूचना पर नंदी गौ सेवा धाम के गौसेवक सिल्लू रजक, अमन यादव एवं विकास जोतवानी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल नंदी बछड़े का प्राथमिक उपचार शुरू किया। घायल बछड़े को नंदी गौ सेवा धाम तक पहुंचाना साधन के अभाव में बड़ी चुनौती बन गया था। इसी दौरान सीवर कार्य में लगी जेसीबी मशीन के चालक ने इंसानियत और गौसेवा की मिसाल पेश करते हुए बिना किसी संकोच के अपनी जेसीबी से घायल नंदी के रेस्क्यू में सहयोग किया। सावधानीपूर्वक जेसीबी की मदद से नंदी बछड़े को सुरक्षित नंदी गौ सेवा धाम पहुंचाया गया।

नंदी गौ सेवा धाम में जारी उपचार और देखरेख

नंदी गौ सेवा धाम पहुंचने के बाद घायल बछड़े का उपचार एवं देखरेख लगातार की जा रही है। इस पूरे सेवा कार्य में गौसेवकों के साथ जेसीबी चालक द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता ने मानवता की एक मिसाल कायम की है। गौसेवकों ने कहा कि किसी बेजुबान जीव की पीड़ा को समझकर उसकी मदद के लिए आगे आना ही सच्ची मानवता है। एक नंदी के जीवन को बचाने के लिए जिस तरह लोगों ने मिलकर प्रयास किया, वह समाज में सेवा, संवेदना और सनातन संस्कारों की भावना को मजबूत करता है। एक जीव को बचाना केवल सेवा नहीं, बल्कि मानवता और सनातन संस्कारों का पालन है। घायल नंदी की मदद के लिए आगे आए सभी सहयोगियों के प्रति गौसेवकों ने हृदय से आभार व्यक्त किया।

सतना के खूंथी में वर्षों से चल रहा अवैध बूचड़खाना

सतना ब्यूरो। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खूंथी मोहल्ले में अवैध बूचड़खाना संचालित होने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां बीच बस्ती में वर्षों से बूचड़खाना चल रहा है जिससे फैल रही गंदगी और दुर्गंध से मोहल्ले के लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस बूचड़खाने का संचालन मुन्ना कुरैशी नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में कलेक्टर नगर निगम कमिश्नर सहित कई अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी जा चुकी हैं लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

लाइसेंस का दुरुपयोग करने का आरोप-शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उक्त व्यक्ति को मुकुंदपुर टाइगर सफारी में वन्य जीवों के भोजन के लिए मांस सप्लाई का लाइसेंस मिला हुआ है लेकिन आरोप है कि आड़ में वह भैंस.पाड़ा काटकर कई जिलों में मांस की सप्लाई कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बकरीद त्यौहार नजदीक होने के कारण अभी से बड़ी संख्या में मवेशी लाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि त्यौहार के दौरान यहां हजारों की संख्या में पशुओं का वध कर मांस की सप्लाई दूर.दूर तक की जाएगी।

प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप-सूत्रों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और संबंधित थाने की अनदेखी के चलते यह अवैध कारोबार बेरोकटोक चल रहा है। उनका कहना है कि बूचड़खाना रिहायशी इलाके के बीचों.बीच होने से रात.दिन दुर्गंध फैली रहती है जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रात में बदबू के कारण नींद तक नहीं आ पाती और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सिंहपुर माँ काली मंदिर में गणेश जी का विधि विधान से की गई पूजा-अर्चना

न्यास के सदस्यो ने विधायक के उपस्थिति मे रखा मुख्यमंत्री को सिंहपुर काली मंदिर बुलाने का प्रस्ताव, विधायक ने दिया हरसंभव प्रयास का भरोसा

शहडोल/सिंहपुर (स्वतंत्रमत)। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ऐतिहासिक सिंहपुर धाम में आस्था के साथ विकास की नई उम्मीद भी जागी। माँ काली एवं भगवान गणेश के प्राचीन मंदिर में दर्शन-पूजन करने पहुंचीं जयसिंहनगर विधायक एवं मध्य प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मनीषा सिंह के समक्ष माँ काली मंदिर लोक न्यास ने मुख्यमंत्री के आगामी शहडोल प्रवास के दौरान सिंहपुर धाम में दर्शन कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे विधायक ने सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए सार्थक पहल का भरोसा दिया। माँ काली मंदिर लोक न्यास, सिंहपुर के विधिवत गठन एवं स्थापना के बाद विधायक मनीषा सिंह का मंदिर परिसर में प्रथम आगमन हुआ। मंदिर पहुंचने पर न्यास पदाधिकारियों, सदस्यों एवं सेवादारों ने आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। विधायक ने माँ काली एवं भगवान गणेश का विधि-विधान से पूजन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की।

धार्मिक विकास को मिलेगी नई दिशा-दर्शन-पूजन के बाद मंदिर परिसर में न्यास पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

इस दौरान सिंहपुर धाम के धार्मिक महत्व, विकास और भविष्य की संभावनाओं को लेकर विचार-विमर्श किया गया। न्यास की ओर से आग्रह किया गया कि मुख्यमंत्री के आगामी शहडोल प्रवास के दौरान उनके सिंहपुर धाम आगमन एवं दर्शन का कार्यक्रम भी निर्धारित कराया जाए। विधायक मनीषा सिंह ने न्यास के आग्रह को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को सिंहपुर धाम लाने की दिशा में शीघ्र सार्थक प्रयास करने का आश्वासन दिया। न्यास पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री का सिंहपुर धाम आगमन इस प्राचीन सिद्धपीठ के धार्मिक एवं पर्यटन विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि अमरेंद्र तिवारी, न्यास उपाध्यक्ष मनीष शुक्ला, सह-सचिव श्रवण श्रीवास्तव, अनूप तिवारी, प्रकाश तिवारी सहित न्यास के पदाधिकारी, सदस्य एवं सेवादार उपस्थित रहे। गणेश चतुर्थी के दिन हुई इस पहल से न्यास परिवार एवं क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि माँ काली और भगवान गणेश की इस पावन धरा को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में अब ठोस कदम आगे बढ़ेंगे।

बुढ़ार चौक-बस स्टैंड मार्ग पर निर्माण की धीमी रफ्तार से बढ़ी परेशानी, व्यापारी बोले, जल्द पूरा हो सड़क कार्य, कलेक्टर को सौंपा आवेदन

शहडोल (स्वतंत्रमत)। बुढ़ार चौक से बस स्टैंड मुख्य मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य में कथित विलंब को लेकर स्थानीय निवासी एवं व्यापारियों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में कलेक्टर को जनहित आवेदन सौंपकर मार्ग की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया गया है। आवेदन में बताया गया है कि सड़क निर्माण के दौरान मार्ग के दोनों ओर बड़े गड्ढे होने से आम नागरिकों का आवागमन जोखिमपूर्ण हो गया है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, मार्ग बाधित होने से एंबुलेंस एवं फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के आवागमन को लेकर भी चिंता जताई गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लगभग 40 दिनों से मार्ग प्रभावित होने के कारण आसपास की दुकानों और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा विद्युत पोल शिफ्टिंग नहीं होने को कार्य में बाधा बताया जा रहा है। इसे लेकर संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई गई है। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से विद्युत पोल जल्द शिफ्ट कराने, निर्माण एजेंसी को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए पाबंद करने तथा निर्माण अवधि में सुरक्षित आवागमन और आपातकालीन सेवाओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर मार्ग को सामान्य आवागमन के लिए खोलने की मांग उठाई गई है।

जनसुनवाई में जिले भर से आए 78 आवेदकों की सुनी गई समस्याएं

कलेक्टर ने की जनसुनवाई, सीईओ जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टरों ने की उपस्थिति

शहडोल (स्वतंत्रमत)। कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिले भर से आए 78 आवेदकों की जनसुनवाई की गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में ग्राम रामपुर, थाना अमलई निवासी घनश्याम नापित ने खपत के अधिक बिजली बिल आने की शिकायत, ग्राम भदवाही तहसील गोहपारू निवासी रामनाथ जायसवाल ने खसरा सुधार करने, ग्राम पंचायत घुनघुटा, ग्राम अतरौड़ी तहसील जैतपुर निवासी रंजीत राय ने ग्राम अतरौड़ी में विद्युतीकरण करने, वार्ड नं. 21 धनपुरी निवासी सलमा बेगम ने रास्ता दिलाने संबंधी, वार्ड नं. 29 शहडोल निवासी निर्मल सिंह ने राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनवाने, ग्राम सिंदुरी जिला शहडोल निवासी सूरज पटेल ने आल्ट्राटेक कोल माइन्स द्वारा सीएसआर फंड का उपयोग स्थानीय ग्रामों के विकास के लिए करने, गीता प्रसाद शुक्ला, हरिनिवास सिंह, बेवा प्रेमाबाई, राम अवतार काछी एवं कमला चतुर्वेदी समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारी जनपद पंचायत सोहागपुर ने सेवानिवृत्त के बाद अवकाश नगदीकरण एवं ग्रेज्युटी राशि का भुगतान संबंधी आवेदन जनसुनवाई में दिए। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

1000 दिवस से अधिक समय तक सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों का किया जाएगा वेतन बंद

निम्नगुणवत्ता से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें बंद करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

शहडोल (स्वतंत्रमत)।

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में आयोजित समय-सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियो को निर्देश दिए कि गत माह से बेहतर परिणाम लाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता के साथ शिकायतें बंद नही की जाएं। निम्नगुणवत्ता से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें बंद करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने एक हजार दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिए कि शिकायतों का आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से निराकरण कर दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि 1000 दिवस से अधिक समय तक सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों से संबंधित अधिकारियों का वेतन बंद किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हाउस, सीएम मानिट तथा विभिन्न आयोगो से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियो को समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को लैंड बैंक की जानकारी देने तथा आबादी भूमि के प्रस्ताव आगामी 10 वर्षों की जरूरत का आंकलन कर जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व काजोल सिंह, अर्चना मिश्रा, वनमंडलाधिकारी उत्तर वन मंडल तरूणा वर्मा, श्रद्धा पंद्रे, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, डिप्टी कलेक्टर भागीरथी लहरे, एंटोनिया एक्का सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहें।

सिंहपुर थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव

भारी संख्या में लोगों ने की नारेबाजी

सतना ब्यूरो। जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर राहुल सिंह की हत्या के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले में निष्पक्ष जांच और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को राजपूत संगठन एवं भारतीय किसान संघ ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दिया। दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हुआ यह प्रदर्शन शाम तक जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपूत संगठन के पदाधिकारियों और भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सिंहपुर और नागौद क्षेत्र के लगभग 300 से अधिक लोग ट्रैक्टर.ट्रालियों में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सिंहपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। थाना प्रभारी पंकज शुक्ला के कार्यकाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं जिसके चलते हिस्ट्रीशीटर राहुल सिंह की हत्या जैसी बड़ी वारदात हो गई।

संगठनों का कहना है कि राहुल सिंह हत्याकांड में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। हत्या के बाद पुलिस ने मामले को दबाने का प्रयास किया और आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसी के विरोध में यह घेराव किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सिंहपुर थाना प्रभारी पंकज शुक्ला को तत्काल थाने से हटाया जाए और पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। जब तक थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

धरने के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सिंहपुर और नागौद क्षेत्र के किसान पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऊपर से पुलिस के रवैये के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। थाने में शिकायत लेकर जाने वाले किसानों और आम लोगों के साथ अभद्रता की जाती है। इसलिए अब किसानों ने आर.पार की लड़ाई का मन बना लिया है।

इधर एसपी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने और ट्रैक्टरों के आने से यातायात व्यवस्था भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुई। स्थिति को संभालने के लिए कोतवाली और सिटी कोतवाली का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पांच सूत्रीय मांगें रखी हैं। जिसमें थाना प्रभारी को हटाने राहुल सिंह हत्याकांड की निष्पक्ष जांच मृतक के परिजनों को सुरक्षा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक और किसानों के साथ थाने में सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की बात सुन ली गई है। राहुल सिंह हत्याकांड में पहले से ही जांच कार्रवाई चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। फ़िलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया है लेकिन संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

बच्चों के मौत की जिम्मेदार भाजपा सरकार, तय करें जिम्मेदारी : जीतू पटवारी

कांग्रेस का शक्ति प्रर्दशन, कलेक्टर को सौंपा मांग पत्र

बालाघाट(स्वतंत्र मत)। जिले में बैगा आदिवासी बच्चें, चावंल घोटाला, डमलमनी काण्ड और किरनापुर थाना में महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर 15 सितम्बर को बालाघाट के आम्बेटकर चौक में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, आखिल भारतीय आदिवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान ओमकार सिंह मरकाम, नारायण सिंह पट्टा विधायक, रजनीस सिंह, जिलाध्यक्ष संजय उइके, मधु भगत, विवेक विक्की पटले, पूर्व सांसद बोधसिंह भगत सहित अन्य ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहें और 32 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी तय करने की मांग रखीं गई। जानकारी अनुसार, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गोंदिया से रजेगांव पहुंचे और फिर बालाघाट के आदिवासी अंचल में बच्चों की मौत को लेकर प्रदेश सरकार पर विरोध प्रर्दशन के लिए बालाघाट पहुंचे और सभा को सबोंधित किया गया। जिसके पश्चात आंबेडर चौक से शक्ति प्रर्दशन रैली निकाली गई और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया।इस दौरान जीतू पटवारी ने कह कि बहुत भयावहता हमारी सरकार की पहचान हैं, बच्चों की हत्या में देश-दुनिया में नम्बर वन बन गई है। बालाघाट में एक साल से 10 साल तक के बच्चें शासन व प्रशासन के भष्टाचार एवं लापरवाही की वजह से तड़प-तड़प कर मर गए हैं। इस दौरान उन्होने कहा कि ये कभी राशन के चांवल, धान 3100 का वादा, बहनों के 3000 देने का वादा, सोयाबिन का छ हजार का वादा भी खा गए और भाषण इनके लम्बे-लम्बे हैं हर जगह सिर्फ चोरी हैं। लेकिन अब वक्त का पहिया बदल गया हैं, भाजपा और मोदी की कलाई खुल चुकी है और राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं वह जनता के दिलों में बैठ चुके है।

बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत हुई वह घटना, दुर्घटना या कोई लापरवाही नहीं हैं बल्कि सुनियोजित अपराध है जो अपराध सरकार के नुमांदों ने किया है। सरकार के भष्टाचार का कैंसर भाजपा के लोगों ने जड़-जड़ तक फैला दिया हैं, उसी के कारण यहां बैगा बच्चों की मौत हुई हैं आदिवासियों में कुपोषण भी इसी का परिणाम हैं।

यहा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी और बिमारी इनको अगर एक साथ ले तो इन तिनों के लिए सरकार अपराधी हैं। पुरे प्रदेश भर के आदिवासी ब्लॉकों में कांग्रेस प्रदेर्शन करेंगी जिनमें गरीबी, रोजगार, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुरे मध्यप्रदेश में केवल बालाघाट में लिपापोती कर यहा टीम गठित कर दे, टीकाकरण कर दे और बालाघाट की स्थती को बेहतर बताकर पुरे प्रदेश में डेमेज कंन्ट्रोल कर दे।

सितपुरा में प्लाई फैक्ट्री से किसानों की फसल बर्बाद प्रशासन मौन

सतना, ब्यूरो। जिले के सितपुरा क्षेत्र में संचालित प्लाई फैक्ट्री के कारण आसपास के किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं डस्ट और केमिकलयुक्त पानी से सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें सूख रही हैं। किसानों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से 24 घंटे धुआं और लकड़ी का बुरादा उड़ता रहता है। यह बुरादा सीधे खेतों में जाकर फसलों पर जम जाता है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। वहीं फैक्ट्री का गंदा पानी नाले के जरिए खेतों में जा रहा है जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही है। धान गेहूं और सब्जी की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं।

फसलें जल रहीं जमीन बंजर हो रही-किसानों ने बताया कि पहले इस क्षेत्र में अच्छी पैदावार होती थी लेकिन जब से प्लाई फैक्ट्री शुरू हुई है तब से पैदावार आधी रह गई है। कई खेतों में तो फसल पूरी तरह से काली पड़कर सूख गई है। पत्तियों पर केमिकल की परत जम जाने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई जांच-किसानों का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कलेक्टर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तहसीलदार को कई बार दी है।

कार्यालय नगरपालिका परिषद् धनपुरी जिला- शहडोल म.प्र.

(कार्यालय दूरभाष नं. एवं फैक्स नं. 07652-250318, E-mail ID-cmodhanpuri@mpurban.gov.in)

क्रमांक/न.पा./लो.नि./2026-27/1109 **निविदा सूचना** धनपुरी दिनांक :- 11.09.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली एवं जेम पोर्टल पर पंजीकृत संविदाकारों से ऑनलाईन जेम पोर्टल के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट GEM Portal पर निम्नानुसार बिड नं. पर देखा जा सकता है।

क्र.	जेम बिड क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	लागत	कार्य की समयावधि	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	BID NO: GEM/2026/B/8021385 Dt 10.09.2026	नगर पालिका धनपुरी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत व्यवस्था हेतु 500 नग 50 वाट एल.ई.डी. लाईट क्रय हेतु	9.80 लाख जी.एस.टी. सहित	कार्यादेश से 15 दिवस	25.09.2026 को 6.00 PM

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन GEM Portal की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिक अधिकारी
नगर पालिक परिषद धनपुरी, जिला शहडोल (म.प्र.)

छात्रों की गूंज को लेकर विजयराघवगढ़ के कॉलेजों में जोरदार जनसंपर्क, छात्रों ने किया उत्साहपूर्वक स्वागत

कटनी (स्वतंत्रमत)।

राहुल गांधी के आह्वान पर 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर आज कटनी जिले के विकासखंड विजयराघवगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं के बीच व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। युवाओं को इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तथा बड़ी संख्या में छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। पूरे प्रदेश में जेन-जेड युवाओं के बीच छात्रों की गूंज को लेकर जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है। पेपर लीक, शिक्षा के बढ़ते व्यापारीकरण, बेरोजगारी तथा केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा जैसे छात्रहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर युवा अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर दिव्यांशु मिश्रा ने कहा कि, आज का जेन-जेड युवा अपने भविष्य को लेकर बेहद सजग और जागरूक है। पेपर लीक और शिक्षा के बढ़ते व्यापारीकरण ने छात्रों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज को मंच देने का जो आह्वान किया है, उसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। विजयराघवगढ़ के कॉलेजों में छात्रों का उत्साह और स्वागत इस बात का प्रमाण है कि युवा अब अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। 19 सितंबर को इंदौर में छात्रों की यह आवाज और मजबूती से गूंजेगी। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल ने कहा किए छात्रों की समस्याएं केवल छात्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के खिलाफ युवाओं को एकजुट होना होगा। विजयराघवगढ़ के छात्रों में कार्यक्रम को लेकर जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि 19 सितंबर को इंदौर में युवाओं की बड़ी भागीदारी होगी। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अजय खटिक ने कहा किए छात्रों की गूंज आज कॉलेज-कॉलेज तक पहुंच रही है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, पेपर लीक पर रोक और शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ छात्र अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। विजयराघवगढ़ के छात्र भी बड़ी संख्या में इंदौर पहुँचकर इस अभियान को मजबूती प्रदान करेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं से अधिक से अधिक संख्या में 19 सितंबर को इंदौर पहुँचकर छात्रों की गूंज को मजबूत बनाने की अपील की गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष यु.का शुभम साहू, शुभम शर्मा, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष राजन साहू, अवध यादव, सौरभ पांडेय, अखिलेश द्विवेदी, विकास सिंह, अभिषेक दुबे, वैभव सिंह बघेल, अमन तिवारी, वीरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

फोटो : विकास गुप्ता

आठ दिवसीय कार्यक्रम का होगा भव्य आयोजन

कटनी (स्वतंत्रमत)। अग्रवाल नवयुवक मण्डलए, अग्रवाल महिला गण्डल कटनी के तत्वाधान में अग्रवाल समाज की एक संयुक्त बैठक सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के मुख्य अतिथि, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल अध्यक्षता, मुरली मनोहर अग्रवाल विशिष्ट अतिथि में गत दिवस अग्रवाल भवन (धर्मशाला) मालवीयगंज में सन्पन्न हुई जिसमें सर्वप्रथम रोहित अग्रवाल सचिव अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा विगत वर्ष का आय व्यय प्रस्तुत किया गया है जो कि सर्वसम्मति से पारित किया गया । अग्रसेन जयंती-2026 पर विस्तृत चर्चा पश्चात् विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 श्री अग्रसेन महाराज जी की जयंती को बड़े ही उल्लास और धूमधाम से मनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। श्री अग्रसेन जयन्ती महोत्सव में आठ दिवसीय कार्यकम का आयोजन होगा जिसमें प्रथम दिवस 27 सितंबर दिन रविवार को विशाल रक्तदान द्वितीय दिवस 3 अक्टूबर दिन शनिवार को अग्रवाल समाज की कुल देवी माता महालक्ष्मी जी का पूजन होगा।

सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखकर किया सोलह श्रृंगार

देर रात तक गीत-भजन, फुलहरा विसर्जन के बाद खोला अखंड व्रत

शिवपार्वती के जयकारों से गूंजा जिला

कटनी (स्वतंत्रमत)। अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना का पर्व हरितालिका तीज सोमवार को जिलेभर में आस्था, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर से लेकर गांवों तक तीज की धूम रही। सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर सोलह श्रृंगार किया और भगवान शिव एवं माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पर्व की तैयारियां रविवार से ही घर-घर शुरू हो गई थीं। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से फुलहरा बांधा और पूजा स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया। दिनभर घरों में गुझिया, मिठाई और अन्य पकवान बनाने की तैयारियां चलती रहीं। पूजा की सामग्री जुटाने से लेकर श्रृंगार और पूजन स्थल की सजावट तक महिलाएं पूरे दिन तीज की तैयारियों में व्यस्त रहीं। सोमवार को सुबह से ही जिले के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की आवाजाही शुरू हो गई। कहीं सामूहिक पूजन हुआ तो कहीं तीज व्रत कथा, भजन-कीर्तन और आरती के आयोजन हुए। महिलाओं ने शिवपार्वती को पुष्प, बेलपत्र, फल और मिठाई अर्पित कर पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख-शांति की कामना की। तीज को लेकर बाजारों में भी खास रौनक रही। मेहंदी, चूड़ी, साड़ी, श्रृंगार सामग्री, फल-फूल और पूजन सामग्री की दुकानों पर दिनभर भीड़ बनी रही। शाम ढलते ही शहर के मोहल्लों और कॉलोनियों के साथ ग्रामीण अंचलों में भी तीज के गीत, भजन और संगीत के कार्यक्रम शुरू हो गए, जो देर रात तक चलते रहे। आज मंगलवार की भोर में महिलाओं ने चौथे पहर का पूजन किया। इसके बाद फुलहरा और पूजन सामग्री लेकर नदी-तालाबों के घाटों पर पहुंचीं। सुबह के समय जिले के विभिन्न घाटों पर मेले जैसा माहौल नजर आया। बड़ी संया में महिलाओं ने विधि-विधान से फुलहरा व पूजन सामग्री का विसर्जन किया। इसके बाद महिलाओं ने अपना अखंड व्रत खोला। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी तप और समर्पण की स्मृति में हरितालिका तीज पर व्रत और शिव-पार्वती पूजन की परंपरा चली आ रही है।

जेपीवी डीएवी विद्यालय में मनाया हर्षोल्लास पूर्ण हिन्दी दिवस

कटनी (स्वतंत्रमत)। जमुना प्रसाद विश्वकर्मा डीएवी विद्यालय में हिन्दी दिवस बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश जोन के क्षेत्रीय निदेशक एवं विद्यालय प्राचार्य एस के सिन्हा की अध्यक्षता में पूर्ण हुआ। प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कक्षा सातवीं एवं आठवीं के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न रोचक और मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं । कक्षा सातवीं की छात्रा प्रियल साहू ने हिन्दी भाषा के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए भाषण की प्रस्तुति दी कक्षा आठवीं की छात्रा मुग्धम पंजवानी ने सुंदर एवं मुग्ध कर देने वाली कविता का वाचन किया। इसी क्रम में सातवीं की छात्राएं सावी बिलैया, सौम्या त्रिपाठी, आरोही बघेल एवं स्वर्णिका त्रिपाठी एवं सुहाने ने दोहों और चौपाई गायन के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी।

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये पंजीयन 10 अक्टूबर तक

कलेक्टर तिवारी ने 51 धान पंजीयन केन्द्र किये निर्धारित

कटनी (स्वतंत्रमत)। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन 15 सितम्बर से शुरू हो रहा है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने किसानों की सुविधा के मद्देनजर जिले में 51 धान पंजीयन केन्द्र निर्धारित किए है।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था-पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था-पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता-किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। कलेक्टर तिवारी ने निर्देशित किया है कि आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखें, जिससे किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिये पंजीयन के दौरान ही 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन-पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

किसानों को करें एसएमएस-विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैंए उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

दो आरोपी धारदार तलवार एवं चाकू के साथ कुठला पुलिस की गिरफ्त में

कटनी (स्वतंत्रमत)। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा (भा.पु.से.) के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में अंकुश एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, उप पुलिस अधीक्षक शिवा पाठक के मार्गदर्शन में कुठला थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में आर्म्स एक्ट के मामले में कार्यवाही करने में सफलता प्राप्त की है । 14 सितंबर के रात्रि में कुठला पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान पहलबान ढ़ाबा के आगे नहर के पास एक लड़का शिब्बू चौधरी पिता बृजमोहन चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी इन्द्रानगर गली नम्बर 9 थाना कुठला का संदिग्ध हालत में मिला जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक धारदार लोहे की तलवार मिली जिसे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 15 सितंबर को भ्रमण के दौरान इन्द्रानगर में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इन्द्रानगर बायपास यात्री प्रतीक्षालय में एक लड़का लोहे का धारदार चाकू लिये है जिसकी सूचना तस्दीक करने पर एक लड़का दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबन्द कर पकड़कर का नाम पता पूछने पर अपने नाम मोहित पटेल पिता दलपत पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी इन्द्रानगर गली नम्बर 4 थाना कुठला का होना बताया जिसके कब्जे से एक नग धारदार चाकू को जप्त किया जाकर गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी कुठला निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में की गई जिसमें सहायक उप निरीक्षक रवि शुक्ला, प्रधान आरक्षक अजय यादव, राहुल मिश्रा, रामेश्वर सिंह, आलोक तिवारी, आरक्षक दुर्गेश सिंह, विवेक शुक्ला, विजय प्रजापति एवं अन्य स्टॉफ की भूमिका सराहनीय रही है।

विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस समारोह 16 सितंबर को, होगा भव्य आयोजन

कटनी (स्वतंत्रमत)। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला कटनी के तत्वावधान में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस समारोह 16 सितंबर, बुधवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। आयोजन ऑडिटोरियम हॉल, बस स्टैंड, कटनी में होगा। आयोजकों के अनुसार स्थापना दिवस समारोह में जिले के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सहभागिता रहेगी। समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां की जा रही हैं तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जा रहा है।

डॉक्टर से मारपीट पर चिकित्सकों में आक्रोश

हटा। सिविल अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर चेतन्य साहू के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से चिकित्सकों में नाराजगी है। इसके विरोध में गुरुवार से दमोह जिले के चिकित्सक काली पट्टी बांधकर ड्यूटी कर रहे हैं। चिकित्सक संगठनों ने चेतावनी दी है कि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। शासकीय चिकित्सक संघ जीडीए आईएमए दमोह और आईडीए दमोह के संयुक्त आह्वान पर जिलेभर के डॉक्टर विरोध में शामिल हुए हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर के साथ मारपीट गंभीर मामला है। ऐसी घटनाओं से चिकित्सकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है।

दो दिन पहले एसडीओपी को सौंपा था ज्ञापन-ड्यूटी डॉक्टर एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मयंक प्यासी ने बताया कि दो दिन पहले एसडीओपी कृष्ण पाल सिंह को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर संघ की एडवाइजरी के अनुसार काली पट्टी बांधकर विरोध शुरू किया गया है। चिकित्सकों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर एसोसिएशन के निर्देश पर आंदोलन के अगले चरण का निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टरों ने बताया कि हटा में पहले से ही चिकित्सकों की कमी है। ऐसे माहौल में चिकित्सकों के साथ हिंसक घटनाएं चिंता का विषय हैं। संगठनों ने आमजन और सोशल मीडिया यूजर्स से भी डॉ. चेतन्य साहू के समर्थन में ब्लैक रिबन लगाकर एकजुटता दिखाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो में अन्य लोग भी दिखे, उन पर भी कार्रवाई होगी।

एसडीओपी कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन से घटना से संबंधित साक्ष्य और वीडियो प्राप्त हुआ है। वीडियो में कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मामले में उनकी भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

हरतालिका तीज पर सुहागिनों ने रखा निर्जला व्रत रख, गौरा-पार्वती की आराधना की

हटा। भादौ मास की तीज पर मनाया जाने वाला हरतालिका व्रत नगर एवं आसपास के क्षेत्र में श्रद्धा और आस्था के साथ परंपरागत रूप से मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने दिनभर निर्जला उपवास रखकर माता गौरा-पार्वती का विधिविधान से पूजन किया और भगवान भोलेनाथ की आराधना कर पति की लंबी आयु एवं सुखी दांपत्य जीवन की कामना की। हरतालिका तीज पर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी महिलाओं द्वारा फूलों से आकर्षक फुलेरा तैयार किया गया। फुलेरे के नीचे मिट्टी से निर्मित गौरा पार्वती की प्रतिमाएं स्थापित कर विशेष पूजन अर्चन किया गया। सुबह से ही महिलाओं ने जलाशयों में स्नान कर व्रत धारण किया और दिन-रात निर्जला उपवास रखते हुए अलग-अलग पहर में अग्निदेव को होम अर्पित किया।

मौत के बाद भी नहीं मिलती सम्मानजनक विदाई

हटा जनपद के कई गांवों में मुक्ति धाम बदहाल

कहीं खेत तो कहीं सड़क किनारे अंतिम संस्कार की मजबूरी

हटा। किसी अपने को खोने का दर्द परिवार के लिए सबसे बड़ा होता है, लेकिन हटा जनपद के कई गांवों में लोगों को इस दुख के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं मुक्तिधाम है तो सुविधाएं नहीं कहीं पहुंच मार्ग नहीं और कहीं मुक्तिधाम के लिए सरकारी जमीन तक उपलब्ध नहीं है। बारिश के मौसम में समस्या और विकराल हो जाती है। पन्नी, तिरपाल और टीन की चादरों के सहारे चिता को बारिश से बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। यह स्थिति केवल एक गांव की नहीं बल्कि जनपद क्षेत्र के कई गांवों की जमीनी तस्वीर सामने आती है।

भिंडारी : तीन किलोमीटर दूर फिर भी सुविधा से दूर-हटा मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित भिंडारी गांव में व्यवस्थित मुक्तिधाम नहीं होने की शिकायत ग्रामीणों ने बताई। ग्रामीणों के मुताबिक मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए उचित रास्ता नहीं है और टीन शेड भी नहीं है। बारिश के दौरान किसी की मृत्यु होने पर कई बार बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है। अत्यावश्यक स्थिति में ग्रामीण टीन की चादरें हाथ में पकड़कर अंतिम संस्कार करने को मजबूर होते हैं। ग्राम पंचायत सचिव गिरजा उपाध्याय के अनुसार गांव का मुक्तिधाम पुराना है और लंबे समय से इसी तरह उपयोग में है। नया मुक्तिधाम बनवाने के लिए पंचायत के पास फिलहाल बजट नहीं है। बोरीकला में दो मुक्तिधाम हैं। एक बोरीकला में और दूसरा समीपस्थ छैवला में बताया गया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों जगह टीन शेड और पक्का शवदाह चबूतरा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बारिश के समय ग्रामीणों को टीन की चादरें ऊपर उठाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सरपंच रामचरण पटेल का कहना है कि गांव का मरघट काफी पुराना है। पंचायत के पास पर्याप्त फंड नहीं होने के कारण आवश्यक निर्माण कार्य नहीं हो पाया।

बोरी खुर्द में समस्या और गंभीर है। सरपंच रामेश्वर पटेल ने बताया कि गांव में मुक्तिधाम के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए ग्रामीण अपने खेतों में अंतिम संस्कार करते हैं। जिन परिवारों के पास स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

सिग्रामपुर के मुक्तिधाम में टीन शेड के नाम पर केवल पाइप का फ्रेम खड़ा है। उसके ऊपर टीन की चादर नहीं है। चारों तरफ पेड़-पौधे खड़े हैं और बारिश में मुक्तिधाम तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ से भर जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक शव को मुक्तिधाम तक ले जाना भी चुनौती बन जाता है। कई बार रास्ते में पैर कीचड़ में धंसने और फिसलने से लोगों के गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे हालात में अंतिम यात्रा भी बेहद कठिन हो जाती है।

मामले में एसडीएम हटा राकेश मरकाम का कहना है कि उनके संज्ञान में यह जानकारी आई है। वे संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करेंगे। गांवों में मुक्तिधाम कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं बल्कि मानवीय गरिमा से जुड़ी मूलभूत जरूरत है। ग्रामीणों की मांग है कि जिन गांवों में मुक्तिधाम नहीं हैं, वहां सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर निर्माण कराया जाए और पुराने मुक्तिधामों में टीन शेड, पक्का चबूतरा, पहुंच मार्ग, प्रकाश एवं अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं।

बरगी थाना क्षेत्र का मामला, जांच में जुटी पुलिस

मां गई तीजा मनाने, इधर बेटी ने लगाई फांसी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। बरगी थाने में टीकाराम सरोतिया उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम तिन्सी ने सूचना देकर बताया कि वह मजदूरी करता है । विगत दिवस वह घर में खाना खा पीकर सो गया था । तीजा त्यौहार होने से पत्नी पूजा करने बाजू वाले घर में चली गई थी। दो बेटियां अलग कमरे में सो गई थी। सुबह देखा तो बहुत देर तक उसकी बेटी दुर्गा सोकर नहीं उठी। जिसे जगाने के लिए वह दुर्गा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। ना खुलने पर जब उसने हाथ डालकर अंदर से साकल को खोल कर देखा तो दुर्गा घर की म्यार में साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर मृत अवस्था में लटकी हुई थी।

आमजनों की समस्याएं सुन त्वरित किया समाधान

नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची 37 शिकायतें

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देश पर अपर आयुक्त सौरभ मिश्रा एवं प्रभारी जनसुनवाई वेद प्रकाश चैधरी ने नागरिकों की समस्याओं को सुना, और अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनका तुरंत समाधान भी कराया। प्राप्त शिकायतों में जल विभाग व भवन शाखा की 6-6, स्वास्थ्य विभाग व कॉलोनी सेल की 5-5 और अतिक्रमण शाखा की 4 शिकायतें शामिल रहीं। इसके अलावा उद्यान विभाग की 2, संभाग क्रमांक 2 की 2 तथा राजस्व, सामान्य, स्थापना, प्रकाश विभाग, संभाग 9 व 15 से संबंधित 1-1 शिकायत दर्ज की गई।

मप्र हाईकोर्ट सहायक ग्रेड-3 भर्ती में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मिली राहत

45 साल तक के अभ्यर्थी भर सकेंगे फॉर्म, बढ़ाई गई अंतिम तारीख

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मप्र हाईकोर्ट की सहायक ग्रेड-3 भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 45 वर्ष तक की आयु वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 16 सितंबर को बिना किसी देरी के आवेदन करने का अवसर दिया जाए। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने की। मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर में सहायक ग्रेड-3 के 1174 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में अलग से छूट नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई थी। विज्ञापन में अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 वर्ष तक आवेदन का अवसर दिया गया है।

उचित राहत देने की मांग

याचिका में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण दिए जाने के बावजूद ऊपरी आयु सीमा में अलग से छूट नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का भी हवाला दिया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास मिश्रा और धीरज तिवारी ने मप्र हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना की न्यायिक भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। संबंधित उच्च न्यायालयों के भर्ती विज्ञापन भी याचिका के साथ प्रस्तुत किए गए। याचिका में मप्र जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016 का हवाला देते हुए कहा गया कि उपयुक्त परिस्थितियों में आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान मौजूद है। इसी आधार पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी उचित राहत देने की मांग की गई।

आवेदन का अवसर देने के निर्देश

याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए बताया गया कि समय रहते राहत नहीं मिलने पर निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके, लेकिन अन्य पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के 45 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर देने के निर्देश दिए हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख पहले 15 सितंबर शाम 5 बजे निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

राज्यपाल का कार्यकाल खत्म चीफ जस्टिस को सौंपा जाए प्रभार

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। मप्र के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का विगत 8 जुलाई कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब तक प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। इसे लेकर मप्र हाईकोर्ट में 8 अगस्त को जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जल्द ही इस मामले में निर्णय आ सकता है। दरअसल, मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मप्र के राज्यपाल का पद संभाला था। उनका पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डॉ. एबी खान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है और उनका कार्यकाल पांच साल का होता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय रायजादा ने दलील दी कि पूर्व राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। मंगलवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।

जिनसार के विद्यार्थियों ने जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को किया जागरूक

विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

हितकारिणी सभा द्वारा संचालित जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च (जिनसार) के विद्यार्थियों ने विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस के अवसर पर लिम्फोमा और सीएलएल के साथ मिलकर आगे बढ़ना विषय पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जानकी रमण अस्पताल में किया । कार्यक्रम में बीएससी नर्सिंग द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य लिम्फोमा एवं क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना था। विद्यार्थियों ने इन रोगों की समय पर पहचान, शीघ्र निदान, उचित उपचार तथा मरीजों और उनके परिवारों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

लिम्फोमा एवं सीएलएल के प्रति किया जागरूक

कार्यक्रम का आयोजन बीएससी नर्सिंग द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा प्रो. डॉ. प्रिंसी शाजी, प्राचार्य के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का समन्वय अरविंद यादव एवं प्रियंका गायकवाड़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने लोगों को लिम्फोमा एवं सीएलएल के प्रति जागरूक करते हुए लक्षणों की समय पर पहचान एवं शीघ्र चिकित्सा परामर्श लेने का संदेश दिया। साथ ही, रोग से प्रभावित मरीजों एवं उनके परिवारों के साथ संवेदनशीलता और सहयोग के साथ खड़े रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा इस पहल ने रोग की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार और मरीजों एवं परिवारों के प्रति भावनात्मक सहयोग के महत्व को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया गया।

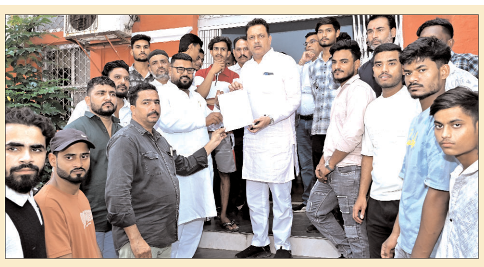

पानी की समस्या को लेकर महापौर से मिले टेड़ीनीम के रहवासी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड स्थित टेड़ीनीम क्षेत्र में पिछले कई दशकों से लगातार हो रही पानी की समस्या की समस्या को लेकर मंगन सिद्दीकी के नेतृत्व में क्षेत्रीय जनता ने महापौर से मिल कर एक ज्ञाप सौंपा। जिसमें बताया गया कि टेड़ीनीम में अमृत जल योजना के अंतर्गत टंकी का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाये। टंकी निर्माण में लगते समय को देखते हुए एक लाइन सिद्ध बाबा मेन रोड से बिछवाने का निवेदन किया। महापौर ने आश्वासन दिया समस्या का निराकरण जल्दी किया जायेगा। इस दौरान जावेद खान, सलमान खान, सिराज़ भाई, गुलाम नबी, अता वारिश, सोनू भाई, नसीम अंसारी सहित क्षेत्रीय लोग शामिल रहे।

जनेकृविवि की कुलसचिव बनी रचना शर्मा

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, जबलपुर में कार्यरत रचना शर्मा को पदोन्नति उपरांत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का कुल सचिव बनाया गया है। आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी एवं एमएससी की शिक्षा प्राप्त की हैं।

12 ट्रेनों की पेंट्रीकारों में मिली गड़बड़ी, लगाया 60 हजार का जुर्माना

जबलपुर स्टेशन पर हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही, सैम्पल किए जब्त

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और पेंट्रीकारों की व्यवस्था को लेकर मुख्य स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान जबलपुर रेल मंडल की टीम ने 12 ट्रेनों के पेंट्रीकारों की जांच की, जिसमें तीन में अनियमितताएं मिलने पर संबंधित संचालकों पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान पके हुए भोजन की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर बिरयानी और सब्जी के नमूने भी लिए गए हैं। नमूने जांच के लिए भेजे गए है, रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

लगातार मिल रही थी शिकायतें - बताया जा रहा है कि रेलवे को लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को पेंट्री कार से बेची जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता खराब होने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। इस पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशांक गुप्ता, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक देवेश सोनी एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक गुन्नार सिंह ने स्टेशन पहुंचकर सघन जांच किया। जांच में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई, खान-पान सेवाओं के निर्धारित मानक और वेंडरों के दस्तावेजों की पड़ताल की गई। इसी तीन ट्रेनों के पेंट्रीकार के अंदर अनियमितताएं मिली। जांच में सामने आया कि गाड़ी क्रमांक 11062 पवन एक्सप्रेस और 11402 पुणे-सुपौल एक्सप्रेस के पेंट्रीकार संचालन का ठेका आइआरसीटीसी ने आरके एसोसिएट को दिया है। वहीं गाड़ी क्रमांक 13202 जनता एक्सप्रेस के पेंट्रीकार का संचालन आइआरसीटीसी की अनुबंधित निजी ठेका एजेंसी पूर्वांचल कैटरर द्वारा किया जा रहा है।

चलती ट्रेन में महिला को हुई प्रसव पीड़ा, रेलवे ने पहुंचाई मदद

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

ट्रेन में यात्रा के दौरान एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर रेलवे द्वारा तुरंत मदद पहुंचाई गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 11055 पर कल्याण से मोहम्मदाबाद की यात्रा कर रहीं 27 वर्षीय श्रीमती रेशमा, जो नौ माह की गर्भवती थीं, उन्हें यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस महत्वपूर्ण सूचना के रेल मदद 139 के माध्यम से प्राप्त होते ही जबलपुर मंडल ने बिना समय गंवाए आवश्यक सहायता की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूचना मिलते ही सतना स्टेशन के उप स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) सक्रिय हुए और स्टेशन पर तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। कुलियों की सहायता से व्हीलचेयर तैयार रखी गई तथा ट्रेन के सतना पहुंचते ही महिला यात्री को अत्यंत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ उनके परिजन सहित ट्रेन से उतारा गया। महिला यात्री को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां उनके लिए एम्बुलेंस पहले से तैयार थी। बिना किसी विलंब के उन्हें उचित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, सतना भेजा गया।

जीसीएफ मुख्य महाप्रबंधक से मिले आईओएफजीओए के पदाधिकारी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) में दिनांक 14 सितंबर 2026 को मुख्य द्वार पर कार्यरत रणजीत प्रजापति के साथ निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना को लेकर आईओएफजीओए ने निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। आईओएफजीओए के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जीसीएफ के मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष एवं गंभीर जांच तथा दोषी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की मांग की। आईओएफजीओए ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों पर फैक्ट्री परिसर में अनुशासन, सुरक्षा एवं उचित आचरण बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटना अत्यंत गंभीर विषय है। संगठन ने मुख्य महाप्रबंधक से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जाए और जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान रघुनंदन पटेल, प्रवीन मिश्रा, दीपक भट्ट आदि उपस्थित रहे।

सैंकड़ों किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सरकार को दिया अल्टीमेटम

एमएसपी पर धान-गेहूं खरीदी की मांग, कलेक्टर को सौंपा 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मंगलवार को सैकड़ों किसानों ने एमएसपी के तहत घोषित दरों पर धान-गेहूं की खरीदी समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामदास पटेल के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि उन्हें भावांतर योजना नहीं, बल्कि एमसपी पर फसल खरीदी की गारंटी चाहिए। उनका कहना है कि मंडियां किसानों के शोषण का माध्यम बन चुकी हैं। प्रदर्शन के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार किसानों ने धान 3100 रुपए और गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की मांग की है। प्रति एकड़ खरीदी की सीमा 25 क्विंटल तय करने को भी कहा। मझौली तहसील में बकाया धान, गेहूं और मूंग का भुगतान तथा पनागर तहसील के विभिन्न वेयरहाउसों की रुकी राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई। ज्ञापन में मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे लगने वाली बोलियों पर रोक लगाने की मांग की गई। किसानों ने व्यापारियों द्वारा माल खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और एफआइआर दर्ज करने की मांग भी रखी।

बिचौलियों पर लगाम लगाने की मांग- किसानों ने मझौली के रानीताल कटाव सबस्टेशन का निर्माण जल्द पूरा कर दिन में 12 घंटे कृषि बिजली देने की मांग की। सिहोरा में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर बदलने और नकली हाइब्रिड बीज बेचने वाली कंपनियों की जांच कर कार्यवाही करने को भी कहा। किसानों ने कहा कि पराली निपटाने के पर्याप्त साधन मिलने तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही किसान खेत सड़क योजना तुरंत शुरू करने की मांग की। प्रशासनिक स्तर पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किसानों ने मंडियों में बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए आधार कार्ड और फोटो स्कैन की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि फसल भुगतान, बिजली आपूर्ति और राजस्व से जुड़ी समस्याओं का समय रहते निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

हितकारिणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक- राम असरानी** द्वारा प्रेस काम्पलेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. **प्रबंध सम्पादक- सुबोध दुबे, सम्पादक- राजेन्द्र मिश्रा,** *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयनार्थ उत्तरदायी। ई-मेल-**smatjbp1@gmail.com,** फोन- 0761-2411414, 4032436 समस्त विवाद जबलपुर न्यायालयाधीन. पोस्टल रजि. नं. एसएसपी जबलपुर/13/2026-28, **RNI No. 64561/96.**